



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 70 ]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 7, 2003/फाल्गुन 16, 1924

No. 70]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 7, 2003/PHALGUNA 16, 1924

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं सम्बद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 मार्च, 2003

अंतिम जाँच-परिणाम

**विषय :** यूरोपीय संघ के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित डी ( - ) पैरा हाइड्रोक्सी फिनाईल ग्लाइसिन बेस ( पी एच पी जी बेस ) के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जाँच।

सं. 14/6/2002-डीजीएडी.—1995 में यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 तथा उसकी सीमाशुल्क टैरिफ ( पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण ) नियमावली, 1995 को ध्यान में रखते हुए :

## क. प्रक्रिया

2. निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई गई—

- निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे इसके बाद प्राधिकारी कहा गया है) को नियमावली के अधीन घेरलू उद्योग की ओर से मै. दौराला आर्मेनिक्स लि., दौराला, मेरठ, उत्तर प्रदेश से लिखित याचिका प्राप्त हुई जिसमें यूरोपीय संघ (जिसे इसके बाद संबद्ध देश/क्षेत्र कहा गया है) के मूल के अथवा वहाँ से निर्यात किए गए डी ( - ) पैरा हाइड्रोक्सी फिनाईल ग्लाइसिन बेस जिसे पीएचपीजी बेस के नाम से भी जाना जाता है (जिसे इसके बाद संबद्ध वस्तु कहा गया है) के पाटन का आरोप लगाया गया है;
- प्राधिकारी ने उक्त नियम 5 के उपनियम (5) के अनुसार जाँच शुरू करने से पहले याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए पाटन संबंधी आवेदन के प्राप्त होने की सूचना भारत में यूरोपीय संघ के शिष्टमण्डल को दी;
- प्राधिकारी ने सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की अनुसूची-I के अध्याय शीर्ष सं. 2942 के अंतर्गत आने वाले डी ( - ) पैरा हाइड्रोक्सी फिनाईल ग्लाइसिन बेस के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जाँच आरम्भ करते हुए दिनांक 8 मार्च, 2002 को भारत के राजपत्र, असाधारण में एक सार्वजनिक सूचना जारी की;

- (iv) प्राधिकारी ने संगत सूचना प्राप्त करने के लिए यूरोपीय संघ के निम्नलिखित ज्ञात नियातकों को प्रश्नावली भेजी :—  
 मै. रिकोरदाती, इटली  
 मै. डीएसएम डेरेटिल एस ए स्पेन  
 दोनों नियातकों से उत्तर प्राप्त हुए हैं।
- (v) नई दिल्ली स्थित यूरोपीय आयोग के शिष्टमंडल को भी जांच अरंभ होने की सूचना दी गई थी और उनसे अपने देश के नियातकों/उत्पादकों से निर्धारित समय के भीतर प्रश्नावली भर कर भेजने का आग्रह करने का अनुरोध किया गया था;
- (vi) संबंद्ध वस्तु के निम्नलिखित उपयोगकर्ताओं/आयातकों को प्रश्नावली भेजी गई थी :—  
 मै. अरबिन्दों फार्मा. लि., हैदराबाद।  
 मै. लूपिन लेबोरेटरीज लि., मुम्बई।  
 मै. कोपरान इम्स लि., रायगढ़।  
 मै. सूर्या फार्मास्यूटीकल लि., चण्डीगढ़।  
 मै. टोरेंट गुजरात बायोटेक लि., अहमदाबाद।  
 मै. रैनबैक्सी लेबोरेटरीज लि., नई दिल्ली।  
 मै. टिनी फार्मा लि. मुम्बई।  
 मै. टोरेंट गुजरात बायोटेक लि. से उत्तर प्राप्त हुआ है। जिनके अनुरोधों का उल्लेख आयातकों के उत्तर में किया गया है। इसके अतिरिक्त किसी अन्य उपयोगकर्ता/आयातक ने प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया है।  
 डी (-) अल्फा पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल ग्लाइसिन  
 डी (-) अल्फा पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल ग्लाइसिन बेस  
 डी (-) पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल ग्लाइसिन  
 पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल ग्लाइसिन  
 डी (-) पी हाइड्रोक्सी फिनाइल ग्लाइसिन बेस  
 डी (-) पी हाइड्रोक्सी फिनाइल ग्लाइसिन आदि
- (vii) निर्दिष्ट प्राधिकारी ने दि. 5 जून, 2002 की अधिसूचना द्वारा प्रारंभिक जांच प्ररिणाम जारी किए तथा प्रारंभिक जांच परिणामों की एक प्रति ज्ञात नियातकों तथा उद्योग संगठनों को भेजी और इस पत्र के जारी होने से 40 दिनों के भीतर उन्हें अपने विचार लिखित रूप में देने का अवसर प्रदान किया।
- (viii) प्राधिकारी ने भारत में पी एच पी जी बेस के ज्ञात आयातकों को सार्वजनिक सूचना की एक प्रति भेजी और उन्हें यह सलाह दी कि वे इस पत्र के जारी होने से 40 दिनों के भीतर अपने विचारों से लिखित रूप में अवगत कराएं।
- (ix) प्राधिकारी ने यूरोपीय आयोग के शिष्टमंडल को प्रारंभिक जांच परिणामों की प्रति उपलब्ध करवाई तथा उनसे यह अनुरोध किया कि वे नियातक तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रारंभिक जांच परिणामों पर अपने विचार प्रस्तुत करने की सलाह दें।
- (x) याचिकाकर्ता से क्षति के संबंध में अतिरिक्त सूचना मांगी गई थी जो प्राप्त हो गई।
- (xi) नियम 6(7) के अनुसार प्राधिकारी ने उसके द्वारा रखी गई सार्वजनिक फाईल के रूप में विभिन्न हितबद्ध पार्टियों द्वारा दिए गए साक्ष्यों का अगोपनीय रूपान्तर उपलब्ध रखा और उसे हितबद्ध पार्टियों द्वारा निरीक्षण के लिए खुला रखा। उन सभी पार्टियों की जिन्होंने फाईल के निरीक्षण के लिए लिखित में अनुरोध किया था, सार्वजनिक फाईल के निरीक्षण की अनुमति दे दी गई।
- (xii) प्राधिकारी ने जांच हेतु आवश्यक समझे जाने वाली सूचना मांगी तथा उसका सत्यापन किया तथा याचिकाकर्ता और इसके साथ-साथ सहयोगी यूरोपियन संघ के स्थल पर जांच की गई थी।
- (xiii) प्राधिकारी ने इष्टतम उत्पादन लागत और परिकलन करने और याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर सामान्यतौर पर स्वीकृत गणना सिद्धांतों के आधार पर भारत में संबंद्ध वस्तु को बनाने और बेचने की लागत की गणना करने के लिए लागत की जांच पड़ताल की।
- (xiv) इस जांच में 1 अप्रैल, 2001 से 31 दिसम्बर, 2001 (9 महीनों) तक की अवधि शामिल है;
- (xv) प्राधिकारी ने सभी हितकर पार्टियों को 17-9-02 को अपने विचार मौखिक रूप से प्रकट करने का अवसर प्रदान किया। मौखिक रूप से विचार व्यक्त करने वाली सभी पार्टियों से लिखित निवेदन दायर करने का अनुरोध किया गया। पार्टियों को, विरोधी पार्टियों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों की प्रतियां एकत्र करने तथा यदि कोई खण्डन है तो उसे प्रस्तुत करने का परामर्श दिया।

(xvi) उपरोक्त नियमावली के नियम 16 के अनुसार इन जांच परिणामों हेतु आवश्यक सभी तथ्यों/आधारों को ज्ञात हितबद्ध पार्टीयों को प्रकट किया गया तथा उस पर ग्राप्त टिप्पणियों को अंतिम जांच परिणामों में उचित रूप से इंगित किया।

(xvii) यह चिन्ह इस अधिसूचना में हितबद्ध पार्टी द्वारा गोपनीय आधार पर दी गई और प्राधिकारी द्वारा नियमों के अंतर्गत रूप में विचार वैसी की गई सूचना का द्योतक है;

(xviii) पी एच पी जी बेस के जांच परिणामों में निम्नलिखित संक्षेपाक्षरों का इस्तेमाल किया गया :

ख. याचिकाकर्ताओं, निर्यातकों, आयातकों तथा अन्य हितबद्ध पार्टीयों के विचार

### 3. जांचाधीन उत्पाद तथा समान वस्तु

आयातक के विचार-मै. टोरेन्ट गुजरात बायोटेक लि. (टीजीबीएल) वदोदरा

(क) जांचाधीन उत्पाद तथा समान वस्तु के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा दिए गए विचारों से हम सहमत नहीं हैं तथा निम्नलिखित निवेदन करते हैं :

ऐसा माना जाता है कि पी एच पी जी बेस से जीवन रक्षक दवाईयों का सीधे निर्माण किया जाता है तथा यह अणु का हिस्सा बनता है। कोटि में थोड़ा-सा भी अंतर दवाई की दक्षता को रोक देगा। पी. एच.पी. के इसकी गुणवत्ता के लिए इसका विवेचनात्मक विश्लेषण किया गया है। यह नोट किया जाए कि अस्वीकृति निम्न कारणों से है।

1. बाहरी वस्तु की विद्यमानता।
2. रंग-ऑफ व्हाइट रंग के परिणाम स्वरूप कम संचरण।
3. विनिर्दिष्ट से अधिक नमी।

सामान्यतः आयातित पी एच पी जी बेस की कोटि देश में उपलब्ध पी एच पी जी बेस की कोटि से उत्तम होती है। इस तथ्य को देश में उपलब्ध सामग्री की विभिन्न खोतों से आयातित सामग्री की कोटि से तुलना करके इस तथ्य को प्रमाणित किया जा सकता है। विशिष्टताएं तथा विभिन्न उपयोक्ताओं की उसकी अनुमत्य सीमा उपयोक्ता दर उपयोक्ता भिन्न हो सकती है। प्रत्येक उपयोक्ता का सामग्री का परीक्षण करने की अपनी प्रणाली होगी अतः एक या दो उपयोक्ताओं द्वारा सामग्री को स्वीकृति देना यह प्रमाणित नहीं करता कि ऐसे महत्वपूर्ण कच्चे माल की कोटि को सभी ने स्वीकृति दे दी है। घरेलू उद्योग का यह विचार कि कुछ बड़े उपयोक्ताओं से माल के लिए बार-बार आर्डर प्राप्त होना माल की कोटि का संकेतक है, यह आवश्यक नहीं। मै. डी ओ एस (दोराला आरगेनिक लि.) द्वारा निर्मित किए जा रहे माल की कोटि का हमारा अनुभव निर्माता के दावे के बिल्कुल विपरीत है।

(ख) अतः हमारी आपसे दुबारा अपील है कि एमोक्सिसिलिन निर्माताओं तथा राष्ट्रहित में यूरोप संघ से आयातित पी एच पी जी बेस पर पाटनरोधी शुल्क लगाने पर पुर्णविचार किए जाए। हम उपर्युक्त मामले पर आपके द्वारा विचार किए जाने की आशा करते हैं।

### 4. घरेलू उद्योग के विचार

वर्तमान जांच में शामिल उत्पाद प्रारंभिक जांच परिणामों अधिसूचना में उल्लिखित इसके कस्टम उपशीर्ष को ध्यान में रखे जिना ढी (-) पैरा हाइड्रोक्स ग्लाइसीन बेस है। इसे सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के (आई टी सी के अधीन 2942.00.29) कस्टम उपशीर्ष 2942.00 के अधीन अन्यों की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। प्रथमतः इसका प्रयोग अमोक्सिसिलिन के उत्पादन में दिया जाता है। परंतु इसका प्रयोग सीधे नहीं किया जा सकता। उत्पाद को पहले ढी (-) पैरा हाइड्रोक्सील फिनाइल ग्लाइसिन मिथाइल पोटाशियम डेन साल्ट, जिसे सामान्यतः पी एच पी जी डीन साल्ट कहा जाता है में परिवर्तित किया जाता है, तत्पश्चात् इसका प्रयोग अमोक्सिसिलिन के उत्पादन में किया जाता है। उत्पाद विशिष्टताओं, कार्य एवं प्रयोग, विपणन, कीमत उपयोक्ता बोध और टैरिफ वर्गीकरण के अर्थों में सम्बद्ध देशों से आयातित पी एच पी जी बेस और घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित पी एच पी जी बेस में कोई वास्तविक अंतर नहीं है। अतः यह निवेदन है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित पी एच पी जी बेस, पाटनरोधी नियमावली के अर्थों के भीतर सम्बद्ध देशों से आयातित पी एच पी जी बेस के समान वस्तु है।

जहाँ तक गुणवत्ता का मामला है, घरेलू उद्योग ने निवेदन किया है कि उन विभिन्न उपयोक्ताओं को पी एच पी जी बेस की पूर्ति कर रहे हैं जिन्होंने न केवल यूरोप में अपितु अमेरिका में विभिन्न प्राधिकारियों को अपने मध्यस्थों की उपयुक्तता के प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए हैं। उन्होंने यह भी निवेदन किया है कि उन्हें भारत में सम्बद्ध वस्तुओं के कुछ बड़े उपयोक्ताओं के बार-बार आर्डर प्राप्त हुए हैं तथा उन्होंने पाया कि उत्पाद की गुणवत्ता न केवल स्वीकार्य है अपितु संतोषजनक भी है।

### 5. प्राधिकारी द्वारा जांच

(क) इस जांच में विचाराधीन उत्पाद पी एच पी जी बेस (पारा हाइड्रोक्सी फिनाइल ग्लाइसीन बेस) है। भारत में सम्बद्ध वस्तु का आयात किया जाता है जिसे बाद में स्वस्थाने पी एच पी जी डीन साल्ट (पीएचपीजीडीएस) में परिवर्तित किया जाता है क्योंकि पीएचपीजी का प्रयोग सीधे ही अमोक्सीलीन आदि के उत्पादन में नहीं किया जा सकता। यह परिवर्तन या तो पीएचपीजी/पीएचपीजीडीएस के विनिर्माताओं की ओर से अथवा प्रयोक्ता अर्थात् अमोक्सिसिलिन आदि के उत्पादकों की ओर किया जाता है। यह सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 29 के अधीन 2942.00 के तहत वर्गीकरण योग्य है। आईटीसी 8-अंकीय वर्गीकरण के अनुसार पीएचपीजी को अध्याय-29 अर्थात् 2942.0029 के तहत अन्य श्रेणियों में किया

जाता है। वर्तमान जांच उस वर्गीकरण पर विचार किए बिना विचाराधीन उत्पाद के खिलाफ है जिसके तहत उसका आयात किया जाता है। सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और वह किसी भी तरह से वर्तमान जांच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

(ख) पाटनरोधी नियम के नियम 2 (घ) में यह विनिर्दिष्ट किया गया है कि समानवस्तु एक ऐसी वस्तु है जो हर तरह से जांचाधीन उत्पाद के समान या समनरूप है अथवा ऐसी किसी वस्तु के अभाव में कोई दूसरी वस्तु जिसमें जांच के अधीन वस्तुओं से अत्यधिक मिलती जुलती विशेषताएं हैं।

(ग) याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि उनके द्वारा उत्पादित वस्तुएं सम्बद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित वस्तु के समान वस्तु हैं। विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु की परिभाषा के बारे में किसी हितबद्ध पार्टी द्वारा कोई विवाद नहीं उठाया गया है। किसी भी हितबद्ध पार्टी इस तथ्य का कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है कि आयातित वस्तुओं से घरेलू तौर पर उत्पादित संबद्ध वस्तु का प्रतिस्थापन नहीं होता है और अपरिकलित गुणता अन्तर से उत्पाद भिन्न नहीं होता प्राधिकारी ने यह निर्धारण किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और बेचे गए पी एच पी जी बेस और आयातित संबद्ध वस्तु को भारत में उपभोक्ताओं द्वारा एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जा रहा है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित पीएचपीजी बेस की विशेषताओं के समान हैं। उपरोक्त के मददे नजर प्राधिकारी यह मानते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित पीएचपीजी बेस तथा सम्बद्ध देशों से आयात किए जा रहे पी एच पी जी बेस क्षति का निर्धारण करने के प्रयोजन से नियमों के अर्थ के भीतर समान वस्तुएं हैं।

#### ग. प्रारंभ आधार और घरेलू उद्योग :

6. पाटनरोधी नियमावली के नियम 2 (ख) के अनुसार घरेलू उद्योग का अर्थ है कि वे घरेलू उत्पादक जो सम्पूर्ण रूप से समान वस्तु के निर्माण और उससे संबंधित किसी भी कार्यकलाप में लगे हुए हैं या वे व्यक्ति जिनका सामुहिक उत्पादन, कुल घरेलू उत्पादन का बड़ा अनुपात है केवल ऐसी स्थिति को छोड़कर जब ऐसे उत्पादक कथित पाटित वस्तु के निर्यातकों अथवा आयातकों से जुड़े हुए हैं या उसके स्वयं आयातक हैं, ऐसे मामले में ऐसे उत्पादक घरेलू उद्योग का हिस्सा नहीं होगे।

घरेलू उद्योग की उपर्युक्त परिभाषा को आगे नियमावली के नियम 5 द्वारा स्पष्ट किया गया है, जिसे निम्नलिखित अनुसार पढ़ा जा सकता है :—

आवेदन घरेलू उद्योग द्वारा या उनकी ओर से माना जाएगा यदि इसका समर्थन उन घरेलू उत्पादकों द्वारा किया गया है जिनका सामुहिक उत्पादन घरेलू उद्योग के उस हिस्से द्वारा उत्पादित समान वस्तु के कुल उत्पादनका 50% का हिस्सा है, वे आवेदन का समर्थन करते हैं या उसका विरोध करते हैं, जैसा भी मामला हो।

याचिका, मै. दोराला आरगेनिक लि. दोराला, मेरठ, उत्तरप्रदेश द्वारा दायर की गई है। याचिकाकर्ता भारत में सम्बद्ध वस्तुओं का एकमात्र उत्पादक है। तदनुसार याचिकाकर्ता उपरोक्त नियमों के नियम 5(3) (क) के अनुसार घरेलू उद्योग की ओर से याचिका दायर करने के आधार का मानदण्ड पूरा करते हैं।

#### घ. जांच की अवधि

7. प्राधिकारी ने जांच की अवधि 1 अप्रैल 2001-31 दिसम्बर, 2001 तक की ली है क्योंकि जांच के लिए यह अभी हाल की अवधि है जब यह मामला 15 फरवरी, 2002 को आरंभ किया गया था। यह अवधि, तिमाही समाप्त होने तथा पूर्ण आंकड़े प्राप्त होने की सहायता के कारण भी ली गई थी। प्राधिकारी ने पुष्टि की है कि पाटनरोधी जांच के लिए नौ महीने की अवधि पर्याप्त तथा न्यायोचित है क्योंकि यह तीन तिमाही के साथ की अवधि है जिसके लिए संगत आंकड़े उपलब्ध हो सकते हैं।

#### ड. अन्य विचार: निर्यातक मै. टोरेन्ट गुजरात बायोटेक लि. के विचार

8. टी जी बी एल, पेन्सिलीन-जी जैसी निर्मित एवं निर्यातित जीवन रक्षक औषधि है तथा इसकी व्युत्पत्ति नामतः आमोक्सिसीलीन ट्राइहाइड्रेट, एन्प्यसिलीन, ट्राइहाइड्रेट, सीफेलेक्सिसल मोनोहाइड्रेट, क्लोमिसिलीन सोडियम, सीफाइड्रोक्सिसल मोनोहाइड्रेट है। निर्माण सुविधा गांव मासर में स्थित है जो गुजरात राज्य के वटोदरा जिला का एक पिछड़ा क्षेत्र है।

पेन्सिलीन आधारित एन्टीबॉयटिक तथा विशेष रूप से अमोक्सिसीलीन ट्राइहाइड्रेट सबसे सस्ती दबाई है, अधिकतर विकासशील देशों में जिसका प्रयोग व्यापक रूप से किया जाता है। देश में अमोक्सिसीलीन ट्राइहाइड्रेट का अनुमानित उत्पादन 4500/5000 एमटी प्रति वर्ष तक है।

अभी तक पीएचपीजी बेस का आयात यूरोप, सिंगापुर, और चीन जनवादी गणराज्य से किया जा रहा है क्योंकि अनुरूप कोटि और मात्रा पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए माल का कोई विश्वसनीय घरेलू स्रोत उपलब्ध नहीं है। चीन जन गणराज्य और सिंगापुर से पीएचपीजी बेस पर पाटनरोधी शुल्क लगाने के कारण हमारे पास यूरोपीय संघ से आयातित माल पर निर्भर रहने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं है। यूरोपीय संघ से आयातित गाल पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से अमोक्सिसीलीन ट्राइहाइड्रेट की घरेलू एवं निर्यात आवश्यकता पूरा करने के लिए पीएचपीजी बेस की उपलब्धता में कमी हो जाएगी।

मैसर्स दोराला आरगेनिक्स लि. के पीएचपीजी बेस की गुणवत्ता अनुकूल नहीं है तथा गुणवत्ता अनुकूलता के लिए उत्पाद को अभी भी स्थिरता दी जानी है। एमोक्सिसीलीन ट्राइहाइड्रेट की गुणवत्ता का पीएचपीजी बेस तथा अन्य कच्चे उत्पाद की गुणवत्ता से सीधा संबंध है।

भारतीय विनिर्माता यूरोप से 12/13 अमेरिकी डालर की दर से पीएचपीजीबेस का आयात कर रहे हैं। दोनों स्रोतों के बीच में अंतर समुद्री भाड़े, जहाजी बीमा, हैंडलिंग प्रभारों तथा व्यापार की अन्य पद्धतियों तथा जिन प्रक्रिया तकनीकों का अनुसरण किया जा रहा है, के कारण हो सकता है।

यूरोपीय संघ से पीएचपीजी बेस के आयात पर प्रस्तावित पाटनरोधी शुल्क कीमत से तकरीबन दुगुना 21.38/21.81 अमेरिकी डालर की दर से है। यह एमोक्सीसीलीन ट्राइहाइड्रेट की कुल उत्पादन लागत बढ़ा देगा जो कि अंतिम उपयोक्ताओं पर नहीं थोपी जा सकती।

इसके कारण घरेलू उद्योग में एकाधिकार की स्थिति उत्पन्न होगी चूंकि घरेलू उद्योग में इस उत्पाद का केवल एक ही आपूर्तिकर्ता है तथा भारत में एमाक्सीसीलीन के सभी विनिर्माताओं को या तो पाटनरोधी शुल्क सहित सामग्री का आयात या अधिक कीमत पर संदेहास्पद सामग्री का इस्तेमाल करना पड़ेगा।

डीओएल की उत्पादन लागत संचालन के स्तर तथा अन्य निवेश लागतों यथा उपयोगिता, श्रम लागत तथा ब्याज पर भी निर्भर करेगी। यह एक जाना माना तथ्य है कि भारत में उपयोगिता लागत तथा ब्याज दरें अन्य देशों की तुलना में बहुत अधिक हैं।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, हम निम्नलिखित कहते हैं :

- (क) यूरोपीय संघ से आयातित पीएचपीजी बेस के लिए अमेरिकी डालर 21.38/21.81 प्रति.कि. पर मनमानी पहुंच कीमत नियत करने में कोई औचित्य नहीं है।
- (ख) यह निष्कर्ष निकालना गलत होगा कि यूरोपीय संघ से भारत को पीएचपीजी बेस का निर्यात सामान्य से कम कीमत पर हुआ।
- (ग) यह मानना भी अनुचित होगा कि यूरोपीय संघ से आयातों के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है जो कि संभवतः संदेहास्पद अनुकूल गुणवत्ता को छोड़ते हुए, उनकी अन्तर्निहित अक्षमताओं, संचालन के स्तर तथा उच्च निवेश लागतों के कारण हो सकती है।
- (घ) इसके विपरीत, यदि पाटनरोधी शुल्क लगाया जाता है तो भारतीय एमोक्सीलीन विनिर्माताओं को बहुत सी कठिनाइयों तथा गैर-किफायती व्यापार स्थितियों का सामना करना पड़ेगा। लागत में वृद्धि का संपूर्ण प्रभाव अंतिम उपयोक्ताओं पर थोपना संभव नहीं होगा।

### प्रकटन के पश्चात आयातक की टिप्पणियाँ—मैसर्स टीजीबीएल, अहमदाबाद

पाटनरोधी शुल्क लगाने पर एमोक्सीलीन ट्राइहाइड्रेट के घरेलू विनिर्माताओं को गुणवत्ता से समझौता करते हुए स्थानीय आपूर्तिकर्ता से कच्चा माल खरीदना पड़ेगा। अन्यथा घरेलू विनिर्माताओं को ए डी डी की अतिरिक्त लागत के साथ उसी सामग्री का आयात करना होगा। इसके अतिरिक्त आयातक ने कहा है कि यह एकाधिकार की स्थिति को प्रोत्साहित करेगा परन्तु आने वाले समय में इसके कारण समान घरेलू सामग्री की कीमतों में वृद्धि होगी।

### च. अन्य विचार : निर्यातक के विचार : मै. रिकोर्डदाती, इटली

9. हम इंजामैटिक तरीके से बीस वर्ष से पीएचपीजी का उत्पादन करते हैं (याचिकाकर्ता का रासायनिक है) और भारतीय बाजार में विश्व बाजार कीमत के अनुरूप औसत कीमत पर पुनः बेच रहे हैं। भारत की पीएचपीजी का हमारा कीमत स्तर ठोस वार्ताओं के जरिए परिकलित होता है जहां अमोक्सी और पेंजी की अंतर्राष्ट्रीय कीमतें तथा आर्डर के अनुसार मात्रा पर गहराई से विचार किया जाता है।

पीएचपीजी तथा डेनसाल्ट के बाजार में वर्तमान परिदृश्य के अनुसार हमने इस बात पर कभी विचार नहीं किया (आपने ही हमें सूचना दी है) कि स्थानीय कंपनी याचिकाकर्ता ने पीएचपीजी विनिर्माताओं के पहले से भीड़भाड़ वाले बाजार में निवेश किया है।

याचिकाकर्ता के निवेश के निर्णय पर हम कोई फैसला नहीं देना चाहते तथापि यह जानकर बहुत निराशा हुई कि भारत में प्राधिकारी को संरक्षण के लिए बुलाया गया है तथा विदेशी कंपनी के हितों के विरुद्ध कार्रवाई करने को कहा गया है।

भारत में बाजार की ओर हमारा रुख हमेशा यथोचित, गंभीर तथा उचित प्रतिस्पर्धा वाली मनोवृत्ति का रहा है। हम यह सुनिश्चित करते हैं कि न तो हमारे पास पाटन की प्रक्रिया में समाप्त करने के लिए संसाधन ही हैं न तो उस याचिकाकर्ता के हितों के विरुद्ध, जिसके लिए हम चाहते हैं कि वह अपनी स्थिति पर पुनर्विचार करे, कार्रवाई करने की कोई इच्छा है।

### प्राधिकारी द्वारा जांच

10. जहां तक आयातक का संबद्ध वस्तुओं को उसके सामान्य मूल्य से कम कीमत पर निर्यात करने का मामला है, प्राधिकारी ने पाया है कि यह मामला व्यापार की सामान्य प्रक्रिया के मद्दे बिक्रियों तथा सामान्य मूल्य से कम कीमत पर निर्यात से संबंध रखता है जिसका निर्धारण निर्यातकों से प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर किया जाएगा न कि आयातकों के दावों द्वारा।

जहां तक अन्य निर्यातक मैसर्स रिकार्डेटी द्वारा उपर्युक्त पैरा 1.12 में की गई टिप्पणियों का मामला है प्राधिकारी नोट करते हैं कि मैसर्स रिकार्डेटी को प्राधिकारी को उत्तर देने के लिए पर्याप्त अवसर दिए गए। तथापि, प्राधिकारी नोट करते हैं कि निर्यातक ने निर्यातक प्रश्नावली का

प्रत्युत्तर नहीं दिया तथा वर्तमान पाटनरोधी जांच में प्राधिकारी को कोई आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए। निर्यातक से किसी प्रत्युत्तर के अभाव में प्राधिकारी को वर्तमान जांच में मैं रिकार्डेटी को असहयोगी मानने के लिए विवश होना पड़ा तथा पाटनरोधी नियम 6(8) के अनुसार निर्यातक से संबंधित सर्वोच्च उपलब्ध सूचना को लिया है।

#### छ. एकाधिकार तथा उठाए गए अन्य मुद्दों के संबंध में प्राधिकारी द्वारा जांच

11. प्राधिकारी ने यह स्वीकार किया है कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से बाजार में उत्पाद की कीमतों पर कुछ प्रभाव पड़ सकता है। परन्तु इसके साथ-साथ प्राधिकारी का विचार है कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से उपयोक्ताओं की संगत प्रतिस्पर्धा पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। आगे आगे वाले समय में उपयोक्ताओं को उचित कीमतों पर माल की पूर्ति सुनिश्चित होगी।

1. यह तथ्य कि देश में सम्बद्ध वस्तुओं का एक उत्पादक है, किसी भी प्रकार पाटनरोधी नियमों के अंतर्गत घरेलू उत्पादक के पाटित आयातों के विरुद्ध प्राधिकारी से सहायता का दावा करने के अधिकार को प्रतिबंधित नहीं करता। यह स्वीकार किया गया है कि पाटनरोधी शुल्क की प्रकृति, पाटन के व्यापार विकृति प्रणाली के विरुद्ध सुधार प्रदान करने की है। इसके अतिरिक्त पाटनरोधी शुल्क किहीं भी ग्रोतों से आयातों को प्रतिबंधित नहीं करता अतः देश में कुल खपत में घरेलू पूर्ति कम हो रही है इसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है। इसके अतिरिक्त चौंक भारतीय उपयोक्ताओं को पूर्ति के बैकल्पिक स्रोत उपलब्ध है अतः इस संबंध में उपयोक्ता उद्योग की आशंका अनुचित है।

2. जहां तक विभिन्न हितबद्ध पार्टीयों द्वारा उठाये गये इस मुद्दे का संबंध है कि घरेलू उद्योग संबंध वस्तुओं का एक अक्षम पूर्तिकर्ता है प्राधिकारी यह मानते हैं कि उन्होंने इष्टतम उत्पादन लागत पर विचार करके क्षति मार्जिन का निर्धारण किया है।

#### 12. पाटन मार्जिन से संबंधित मुद्दे

##### निर्यातक मै. डीएसएम डेरेटिल के विचार

डीएसएम डेरेटिल प्रारंभिक जांच परिणामों से यह जानकर चकित हुआ कि प्राधिकारी ने 6.68% का अस्थायी पाटन मार्जिन निर्धारित किया था। यह जांच परिणाम पूर्णतः गलत, गैर-कानूनी तथा मनमानी है जिसका कोई आधार नहीं है। पाटन मार्जिन निम्न कारणों से निर्धारित किया गया है (i) सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु तीसरे देश का स्वेच्छा से चयन, (ii) भारत को सूचित समुद्री भाड़े की स्वेच्छा से अस्वीकृति तथा (iii) कमीशन के रूप में निर्यात कीमत से 3% की कटौती। स्पष्टीकरण (ग)(i) के अनुसार सामान्य मूल्य निर्यातक देश या क्षेत्र में बेचे जाने वाली समान वस्तु हेतु व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में तुलनात्मक कीमत है। यदि निर्यातक के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान उत्पाद की कोई बिक्री नहीं है। (जैसाकि इस मामले में है) तो स्पष्टीकरण (ग)(ii) में सामान्य मूल्य निर्धारित करने के दो विकल्प दिए गए हैं। स्पष्टीकरण (ग)(ii)(क) जो संगत है, में, उपयुक्त तीसरे देश को समान वस्तु निर्यात किए जाने की तुलनात्मक कीमत के संदर्भ में सामान्य मूल्य निर्धारित करने का प्रावधान है। दूसरे शब्दों में यदि निर्यात बिक्री एक से अधिक तीसरे देश को है तो यह जांच प्राधिकारी पर निर्भर है कि सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए किस देश का प्रयोग किया जाना चाहिए। इस प्रकार निर्धारित देश को इस आवश्यकता को पूरा करना होगा कि यह एक उपयुक्त तीसरा देश है तथा उस देश की कीमत निर्धारित कीमत है। डीएसएम डेरेटिल ने भारत को तथा विश्व के दो अन्य देशों को पीएचपीजी का निर्यात किया था। इन्होंने अपने घरेलू बाजार (ई यू) सहित किसी अन्य देश को पीएचपीजी नहीं बेचा था। अतः सबाल यह है कि सामान्य मूल्य निर्धारण के लिए किन दो तीसरे देशों का प्रयोग किया जाना चाहिए। प्राधिकारी ने स्वेच्छा से दो देशों में से एक को ले लिया है क्योंकि उस देश की कीमत भारत की कीमत से थोड़ी अधिक है।

उपर्युक्त अनुरोध पर पूर्वाग्रह किए बिना यह निवेदन किया गया है कि जांच प्राधिकारी ने तीसरे देश की जिस कीमत पर विचार किया है वह भारत की कीमत से करीब 1% अधिक है। इसने कम कीमत अंतर के परिणामस्वरूप पाटन मार्जिन 2 % के न्यूनतम स्तर तक नहीं हो सकता। डीएसएम डेरेटिल ने अपने इस निवेदन को दोहराया है कि सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए अन्य तीसरे देश की निर्यात कीमत का प्रयोग किया जाना चाहिए।

डीएसएम डेरेटिल ने जांच अवधि के दौरान भारत को सम्बद्ध वस्तुओं का केवल एक परेषण निर्यात किया था। प्राधिकारी ने दो को छोड़कर इस निर्यात कीमत को तथा उस पर दावा की गई कटौतियों को स्वीकार कर लिया था। वास्तव में इन दो अंतरों की वजह से पाटल मार्जिन हुआ, ये दो अंतर (क) समुद्री भाड़े और (ख) कमीशन के संबंध में हैं। डीएसएम डेरेटिल ने समुद्री भाड़े के लिए कटौती का दावा किया है। डीएसएम डेरेटिल ने सिपिंग कम्पनी द्वारा जारी बीजक जिसमें समुद्री भाड़े और अन्य व्यय के ब्यौरे दिए गए हैं, संलग्न किया है। दूसरे शब्दों में समुद्री भाड़े पर कटौती के रूप में दावा को गई राशि के भुगतान के लिए वास्तविक साक्ष्य प्रारंभिक प्रश्नावली प्रत्युत्तर में संलग्न किए गए थे। पोतवणिक द्वारा दिए गए वास्तविक बीजक से अच्छा साक्ष्य नहीं हो सकता।

प्राधिकारी इस बात को समझते होंगे कि समुद्री भाड़ा केवल तय की गई दूरी पर निर्भर नहीं कर सकता। यह दो बंदरगाहों के बीच पोत/जहाज के आगे-जाने की संख्या पर निर्भर करता है। वार्सिलोना और भारत के बीच यात्रा करने वाले जहाजों की संख्या वार्सिलोना तथा निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा चयनित तीसरे देश के बीच आगे-जाने वाले जहाजों की संख्या से बहुत अधिक है। इसके साथ-साथ भारत के लिए तथा ऐसे अन्य

बंदरगाहों के लिए जहां बार-बार लदान किया जाता है का भाड़ा कम नौवहन किए जाने वाले स्थानों से बहुत कम है।

कथित बीजक से प्राधिकारी ने नोट किया कि न्हावाशेवा पोर्ट से नई दिल्ली तक अंतर्देशीय परिवहन भारत के समुद्री भाड़े के लगभग समकक्ष है। बासीलोना तथा न्हावाशेवा के बीच के अंतर से कहीं ज्यादा है। इसलिए प्राधिकारी दोनों ही परिवहन आंकड़ों को अस्वीकार नहीं कर सकते।

प्रारंभिक जांच परिणामों के पैरा 17 से पता चलता है कि प्राधिकारी ने कमीशन के लिए कटौती की है। इस बारे में कोई कारण नहीं दिया गया कि कटौती किस दर से कमीशन के लिए सी आई एक कीमत का 3% कम किया है।

प्रत्युत्तर के परिशिष्ट 4 में डी एस एम डेरेटिल ने 'ओ' के आंकड़े 'छूट/कमीशन' के विरुद्ध वर्गीकृत रूप से सूचना दी है। जबकि निर्यातक, जिसे तथ्यों का ज्ञान है, स्पष्टतः यह सूचना देते हैं कि कोई कमीशन नहीं दी गई है, इस बारे में कोई ज्ञान नहीं है। यह प्रक्रिया फिर से प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह कटौती डी एस एम डेरेटिल के लिए किसी भी तरह से पाठन मार्जिन के निर्धारण के एकमात्र उद्देश्य से की गई है।

डी एस एम डेरेटिल न तो स्पेन में और न ही यूरोपीय संघ में पी एच पी जी बेस का विक्रय करता है। इसने पी एच पी जी बेस के बाल भारत में और विश्व में अन्य दो देशों को बेचा है। निर्दिष्ट प्राधिकारी को अन्य दोनों देशों को किए गए निर्यातों के सौदेवार ब्यौरे उपलब्ध करवाए गए।

डी एस एम डेरेटिल पर अपने विक्रय प्रबंधों का खुलासा न करने अपितु केवल संगत साक्ष्य उपलब्ध करवाने का आरोप लगाया गया है। इस बात का उल्लेख करना महत्वपूर्ण होगा कि डी एस एम डेरेटिल ने जांच अवधि के दौरान भारत में केवल एक ही प्रेषण किया था। इस सौदे के लिए संगत साक्ष्य उपलब्ध करवाए गए हैं जो कि बिक्री व्यवस्था का साक्ष्य भी है। बिक्री व्यवस्था का आलेख भाग तभी संगत माना जाएगा जबकि उसमें भिन्न प्रकार के उपयोक्ताओं को भिन्न-भिन्न परिदान/अदायगी इत्यादि की शर्तों के साथ पृथक बिक्रियां की गई हों। इस मामले में ऐसा नहीं है। एकमात्र आपूर्ति अंतिम उपयोक्ताओं को की गई है तथा भागपत्र, बीजक इत्यादि की प्रतियां प्रत्युत्तर के भाग के रूप में उपलब्ध करवाई गई हैं। निर्यातक ने इस बिक्री पर कोई भी कमीशन न दिए जाने के बारे में वर्गीकृत विवरण दिया है।

डी एस एम डेरेटिल द्वारा दिया गया निवेदन अब यह खुलासा करता है कि आई सी डी, दिल्ली को सामग्री सुपुर्द की गई थी, बिल्कुल गलत है। यह सूचना मूल प्रश्नावली के भाग के रूप में उपलब्ध करवाई गई थी तथा डी ए को इसकी जानकारी है।

पैरा 5 में प्रकथन कि खाड़ी देशों को की गई बिक्रियों पर सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए विचार किया जाना चाहिए बिल्कुल गलत है। पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध 1 के पैरा 6 (i) में प्रावधान है कि जहां तक संभव हो सके एक ही समय पर की जाने वाली बिक्रियों के संबंध में तुलना की जानी चाहिए। पैरा 6 (iv) में यह भी प्रावधान है कि पाटन मार्जिन का निर्धारण सामान्य मूल्य और भारित औसत निर्यात कीमत के बीच तुलना के आधार पर किया जाना चाहिए। भारित औसत के परिकलन में जांच अवधि के नौ महीने के दौरान किए गए सभी सौदों का समेकन आवश्यक माना जाता है। पैरा 6 (iv) में यह भी प्रावधान है कि पाटन मार्जिन का निर्धारण सामान्य मूल्य सौदे का निर्यात कीमत सौदे के साथ तुलना करके किया जा सकता है। दोनों प्रावधानों अर्थात् पैरा 6 (i) और 6 (iv) को सुव्यवस्थित ढंग से एक साथ पढ़ा जाना चाहिए। प्राधिकारी ने पाटन मार्जिन का निर्धारण भारित औसत से भारित औसत प्रणाली के आधार पर किया है, न कि प्रत्येक सौदे की प्रणाली के आधार पर।

उपयुक्त तीसरे देश का निर्धारण भारत तथा तीसरे देश की बाजार परिस्थितियों के संदर्भ में किया जाना चाहिए। कीमत की नियामकता दो देशों में प्रतिस्पर्धा की परिस्थितियों अनुसार निर्धारित किए जाने की आवश्यकता है।

यह आरोप कि निर्यातक द्वारा दी गई उत्पादन लागत संदेहास्पद है, आपित्तजनक है। जहां तक जांच अवधि के तुलनपत्र और लाभ एवं हानि लेखे का संबंध है, प्राधिकारी जिन्होंने 90 से अधिक जांच की हैं यह अच्छी तरह जानते हैं कि कोई भी कम्पनी प्राधिकारी द्वारा निर्धारित जांच अवधि या जांच किए जा रहे उत्पाद के लिए लाभ एवं हानि लेखा और तुलनपत्र तैयार नहीं करते। हमारे द्वारा प्रस्तुत उत्पादन लागत के पर्याप्त साक्ष्य हैं तथा निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा सत्यापन के लिए रखी हुई है।

डी एस एम डेरेटिल द्वारा प्रस्तुत प्रत्युत्तर पर्याप्त एवं विश्वसनीय है। हमने प्राधिकारी द्वारा पूछी गई आज तक की सभी उचित एवं पर्याप्त सूचना उपलब्ध करा दी है। अतः हमने निर्दिष्ट प्राधिकारी से इस सूचना को सत्यापित करने और जहां तक डी एस एम डेरेटिल का संबंध है जांच परिणामों को रद्द करने का अनुरोध किया था।

#### प्रकटन विवरण के पश्चात् निर्यातक की टिप्पणियाँ

उन्होंने जांच समाप्त करने का अनुरोध किया है क्योंकि पाटन मार्जिन न्यून है। उन्होंने यह भी जोड़ा है कि सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए \*\*\*\*\* से अधिक उपयुक्त है।

### ज. घरेलू उद्योग के विचार :

13. कम्पनी ने अन्य देशों को सौदेवार निर्यात के ब्यौरे प्रस्तुत नहीं किए हैं। चूंकि निर्यातक ने यह दावा किया है कि निर्यातक की कोई घरेलू बिक्री नहीं हुई इसलिए उक्त निर्यातक अन्य देशों को हुए निर्यातों के सौदेवार ब्यौरे उपलब्ध कराने के लिए आध्य है। यह नोट करना प्रासंगिक है कि जब जक निर्यातक अन्य देशों को हुए निर्यातों के सौदेवार ब्यौरे उपलब्ध नहीं कराता है तब तक निर्यातक द्वारा यह सिद्ध नहीं किया जा सकता कि अन्य देशों को इसकी बिक्रियां व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में हुई थीं।

निर्यातक ने अपनी बिक्री व्यवस्था का खुलासा नहीं दिया है। केवल संगत साक्ष्य ही गोपनीय आधार पर उपलब्ध कराए गए हैं। तथापि निर्यातक द्वारा ब्यौरे के भाग की अनदेखी कर दी गई है। प्रश्नावली का उत्तर इतनी ही सीमा तक अधूरा है। इस प्रकार याचिकाकर्ता यह समझने में असमर्थ है कि निर्यातक ने किस प्रकार व्यापार किया है। यह निर्यातक के इस दावे के मद्देनजर और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है कि इसने सभी बिक्रियों के सम्बन्ध में किसी कमीशन का भुगतान नहीं किया है। निर्यातक ने अब यह 'खुलासा' किया है कि सामग्री का निर्यात कम्पनी द्वारा किया गया था जिसकी सुपर्दगी आई सी डी, दिल्ली को की गई थी। मौखिक सुनवाई के समय निर्यातक द्वारा उल्लिखित बीजक से यह पता चला कि उसमें यूरोपीय संघ से मुम्बई तक का अंतर्देशीय भाड़ा निहित है। निर्यातक की इस अभिव्यक्ति से सी आई एम निर्यात कीमत में से निर्यातक द्वारा कमी की मात्रा के बारे में एक प्रमुख मुद्दा उत्पन्न होता है। ई यू पत्तन से दिल्ली तक का भाड़ा (समुद्री एवं अंतर्देशीय) यूरोपीय संघ से मुम्बई तक के समुद्री भाड़े की तुलना में काफी अधिक है। याचिकाकर्ता इस सम्बन्ध में विस्तृत जांच की मांग करता है।

निर्यातक ने अपना बिक्री प्रबंध प्रकट नहीं किया है। गोपनीय आधार पर केवल संगत साक्ष्य प्रदान किए गए हैं। परंतु निर्यातक ने आलेख भाग को अनदेखा किया है। अतः प्रश्नावली का उत्तर इस सीमा तक अपर्याप्त है। अतः याचिकाकर्ता यह समझ नहीं पाया कि निर्यातक ने व्यापार कैसे किया। निर्यातक के इस दावे को देखते हुए यह और भी महत्वपूर्ण है कि सभी बिक्रियों के संबंध में उसने कोई कमीशन नहीं दिया है। निर्यातक ने अब प्रकट किया कि माल कम्पनी द्वारा वितरित किया गया। मौखिक सुनवाई के समय निर्यातक द्वारा प्रस्तुत किए गए बीजक से पता चलता है कि उसमें यूरोपीय संघ से मुम्बई तक समुद्री भाड़ा शामिल है और मुम्बई से दिल्ली तक अंतर्देशीय भाड़ा शामिल नहीं है। निर्यातक द्वारा किए गए इस रहस्योदयाटन से सी आई एफ निर्यात कीमत में से निर्यातक द्वारा की गई कटौती की मात्रा के संबंध में एक मुख्य मुद्दा उत्पन्न होता है। यूरोपीय संघ की बंदरगाह से दिल्ली तक का भाड़ा (समुद्री और अंतर्देशीय) यूरोपीय संघ से मुम्बई तक के समुद्री भाड़े की तुलना में बहुत अधिक है। याचिकाकर्ता ने इस संबंध में विस्तृत जांच का अनुरोध किया है।

याचिकाकर्ता ने दो अन्य देशों को निर्यातों के मामले में निर्यातक द्वारा दावा किए गए भाड़े का परिकलन किया है। याचिकाकर्ता को यह जानकर दुख हुआ कि निर्यातक ने खाड़ी देश के मामले में अनुमानित भाड़े का दावा किया है जो भारत के मामले में शामिल समुद्री भाड़े से लगभग पांच गुना बंदरगाह तक निर्यातक द्वारा दावा किया गया भाड़ा इतना अधिक है कि जिसकी कल्पना थी नहीं की जा सकती। यही कारण है कि याचिकाकर्ता इस संबंध में भाड़े के साक्ष्य प्रस्तुत करने पर जोर डाल रहा है। परन्तु निर्यातक ने जानबूझ कर यह सूचना प्रदान नहीं की है।

जहां तक निर्यातक के इस तर्क का संबंध है कि सामान्य मूल्य का मूल्यांकन देश पर आधारित होना चाहिए, याचिकाकर्ता का अनुरोध है कि सामान्य मूल्य योरापीय संघ से देश-2 को निर्यात बिक्री के आधार पर किया जाना चाहिए। देश-2 को की गई बिक्री का समय वही था जो भारत को निर्यात का था।

निर्यातक द्वारा उत्पन्न लागत के संबंध में प्रदान की गई सूचना पर याचिकाकर्ता ने शंका व्यक्त की है। इसके अतिरिक्त सूचना केवल पी एच पी जी बेस तक सीमित है तथा अन्य उत्पादों के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई है।

निर्यातक ने जांच अवधि का तुलनपत्र और लाभ एवं हानि वितरण प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त लाभ एवं हानि विवरण विचाराधीन उत्पाद के लिए नहीं है। इस संबंध में यह नोट करना प्रासंगिक होगा कि कम्पनी बहुउत्पाद कम्पनी है। अतः कम्पनी द्वारा प्रयुक्त आवंटन और विभाजन आधार महत्वपूर्ण है। संभव है कि लागत के कुछ घटक संबद्धता से प्रभावित हैं। इस प्रकार केवल कम्पनी द्वारा दायर विवरण को निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा आवश्यक सूचना मंगाए बिना तथा आंकड़ों का सत्यापन किए बिना स्वीकार नहीं किया जा सकता। अतः याचिकाकर्ता ने निवेदन किया है कि उत्पादन लागत पर विस्तृत सूचना निर्यातक से एकत्रित किए जाने की आवश्यकता है।

मैं० रिकोडिट्री, इटली ने प्राधिकारी द्वारा प्रस्तावित रूप एवं तरीके से प्रस्तुत नहीं की है। यह प्रारंभिक जांच परिणामों से भी पता चलता है। अतः निर्दिष्ट प्राधिकारी उचित उपलब्ध सूचना पर कार्रवाई करने में पूर्णतः न्यायोचित है। रिकोडिट्री यूरोपीय संघ से भारत को पी एच पी जी बेस निर्यात के मुख्य निर्यातक है। जांच अवधि के दौरान भारत के 144000 कि.ग्रा. के कुल निर्यातों में डी एस एम द्वारा निर्यातित माल का हिस्सा केवल 9000 कि.ग्रा. है। अतः यह कहा जा सकता है कि सम्बद्ध देशों से सम्बद्ध वस्तुओं के अधिकतर निर्यातकों ने निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रत्युत्तर नहीं दिया है।

### प्रकटन के पश्चात् घरेलू उद्योग की टिप्पणियां

- मैसर्स डी ओ एल ने यह मानते हुए, न कि स्वीकार करते हुए निवेदन किया है कि कंपनी ने इस मांगपत्र के लिए कोई कमीशन नहीं किया, सत्य यह है कि यह आदेश किसी मांगकर्ता एजेंट के जरिए प्राप्त किया गया था तथा एजेंट द्वारा दी जाने वाली ऐसी सेवाओं के विरुद्ध प्रतिफल के रूप में दी जाने वाली कमीशन की राशि में समायोजन की आवश्यकता है।

2. घरेलू उद्योग ने कहा है कि निर्यातक की याचिका के परिशिष्ट 7 तथा परिशिष्ट 8, 9 व 10 से संबंधित सूचना में कोई बदलाव है तो निर्यातक का संपूर्ण प्रत्युत्तर अस्वीकार कर देना चाहिए।

### झ. प्राधिकारी द्वारा जांच

14. धारा 9 क (I) (ग) के अन्तर्गत किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का अभिप्राय :—
- सामान्य व्यापार के दौरान वस्तुओं के लिए उप-धारा (6) के अंतर्गत बने नियमों के अनुसार यथानिश्चित तुलनात्मक मूल्य से है जबकि ऐसी वस्तु निर्यातक देश या क्षेत्र में उपभोग के लिए अभिप्रेत हो, या
  - जब निर्यातक देश या क्षेत्र के स्वदेशी बाजार में सामान्य व्यापार के दौरान समान वस्तु की कोई बिक्री नहीं हो या बाजार की विशेष स्थिति के कारण अथवा निर्यातक देश या क्षेत्र के स्वदेशी बाजार में बिक्री की कम मात्रा के कारण, ऐसी बिक्रियों की समुचित तुलना की अनुमति नहीं देती है।
  - निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से आयात किये जाने पर समान वस्तु की उपधारा (6) के अंतर्गत बने नियमों के अनुसार यथानिश्चित तुलनात्मक सादृश्य मूल्य, अथवा
  - उपधारा (6) के अंतर्गत बने नियमों के अनुसार यथानिश्चित, प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य मूल्य एवं लाभों के लिए उचित वृद्धि के साथ-साथ उद्गम देश में उक्त वस्तु के उत्पादन की लागत से हैं—

बशर्ते कि वस्तु का आयात जब मूलता के देश से भिन्न अन्य किसी देश से किया गया हो तथा जहां वस्तु निर्यात के देश से केवल गुजरी हो या ऐसी वस्तु निर्यात के देश से उत्पादित नहीं होती है या निर्यात के देश में उसका कोई तुलनात्मक मूल्य नहीं हो तो इसके सामान्य मूल्य का निर्धारण मूलता के देश में इसके मूल्य के संदर्भ में किया जाएगा।

मैं डी एस एम डेरेटिल, एस.ए. स्पेन

### 15. सामान्य मूल्य

मैं, डी एस एम डेरेटिल ने उत्तर दिया है कि उनकी कोई घरेलू बिक्री नहीं होती है। प्रश्नावली के उत्तर में उन्होंने निर्धारित प्रपत्र में सूचना दी है। परिशिष्ट-1 के अनुसार उन्होंने उत्तर दिया है कि उनकी कोई घरेलू बिक्री नहीं होती है और उन्होंने यह भी कहा है कि उनकी यूरोपीय संघ में इस उत्पाद की कोई बिक्रियां नहीं हुई हैं। परिशिष्ट-3 के अनुसार उन्होंने अन्य देशों और भारत को की गई अपनी बिक्रियों के लेखे दिए हैं, जिसे आगे बिक्रियों के महाबार ब्यौरों में अलग-अलग कर दिया गया। परिशिष्ट-4 और 6 में उन्होंने भारत और अन्य देशों को की गई बिक्रियों के लिए कीमत ढांचे और बिक्री व्यवस्था के बारे में बताया है। प्रारंभिक जांच परिणामों के समय प्राधिकारी ने नोट किया कि निर्यातक ने प्रश्नावली परिशिष्ट-7 के संबंध में अपूर्ण सूचना नहीं दी है। परिशिष्ट 8 और 10 के अनुसार निर्यातक ने वित्तीय और व्याज लागतों के संबंध में पूर्ण सूचना नहीं दी है। यद्यपि निर्यातक ने तीसरे देश को निर्यात की महीने वार सूचना प्राप्त की है परंतु उन्होंने तीसरे देश के संबंध में देशवार तथा सौदावार सूचना प्रस्तुत नहीं की थी।

प्रारंभिक जांच परिणामों के पश्चात् निर्यातक ने निर्यातक प्रश्नावली के परिशिष्ट-7 के संबंध में पूर्ण सूचना प्रस्तुत की थी। निर्यातक ने जांच अवधि के दौरान तीसरे देश को निर्यात के संबंध में सौदेवार सूचना भी प्रस्तुत की है। अन्य उत्पादों के लिए मात्रा और मूल्य के संबंध में भी सूचना प्रस्तुत की गई है। प्रारंभिक जांच परिणामों के पश्चात् उन्होंने निर्यातक प्रश्नावली के परिशिष्ट 8 और 10 से संबंधित वित्त एवं व्याज लागतों के संबंध में सूचना प्रस्तुत की है। उन्होंने पिछले तीन वर्षों के लिए तुलना पत्र और लाभ एवं हानि लेखों के बारे में भी सूचना प्रस्तुत की है। प्रकटन के पश्चात् घरेलू उद्योग द्वारा दी गई याचिका के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि निर्यातक द्वारा ये याचिका सार्वजनिक सुनवाई के बाद ही दी गई तथा प्राधिकारी ने इन अंतिम जांच परिणामों में उसके समस्त रखे सभी निवेदनों पर विचार कर लिया है।

प्राधिकारी नोट करते हैं कि फर्म ने अन्य देशों और भारत को किए गए निर्यातों के लिए कीमत ढांचे के संबंध में विस्तृत सूचना प्रस्तुत की है। प्राधिकारी ने, अन्य देशों को किए गए निर्यातों के सौदेवार ब्यौरों के संबंध में निर्यातकों के स्थलों पर मूल दस्तावेजों का भी सत्यापन किया है। सत्यापन दल ने भारत को निर्यातित पोषण पर दिए गए भाड़े तथा इस सौदे पर कोई कमीशन का भुगतान न किए जाने के लिए डी एस एम डेरेटिल द्वारा किए गए दावे के समर्थन में साक्ष्य की जांच की। सत्यापन दल ने डी एस एम डेरेटिल की आर्डर प्रणाली और भारत में निर्यातक के वही लेखों की भी जांच की है। सत्यापन दल ने मांगकर्ता एजेंट के जांच अवधि के बही लेखों को भी सत्यापित किया था तथा उसके पश्चात् की अवधि में निर्यातक द्वारा यदि कोई कमीशन दिया गया है तो उसकी भी जांच की। सत्यापन दल ने भारत तथा अन्य देशों के लदान के लिए मै. ग्लोबल कनेनर एजेंसी-एस ए द्वारा दिए गए बीजकों की भी जांच की है। सत्यापन दल ने अन्य उत्पादों से संबंधित इस अवधि के लिए अन्य बीजकों की जांच द्वारा न्हावाशेवा से नई दिल्ली तक समुद्री भाड़े की उपयुक्तता की भी जांच की। सत्यापन दल ने उत्पादन लागत आंकड़ों का पता लगाने के लिए जांच अवधि के आंकड़ों की रिपोर्टिंग प्रणाली की भी जांच की।

उपर्युक्त जांचों के आधार पर प्राधिकारी ने इस निर्यातक के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण, निर्यातक देश या क्षेत्र से समान वस्तु के निर्यात की तुलनात्मक प्रतिनिधि कीमत द्वारा किया है। प्राधिकारी ने निर्धारित किया है कि मै. डी एस एम ने जांच अवधि के दौरान \*\*\*\* देश को ग. \*\*\*\* कि.ग्रा. संबद्ध वस्तुओं का निर्यात \*\*\*\* अ.डा. पर किया है। प्राधिकारी ने ईरान को उपर्युक्त तीसरे देश के रूप में स्वीकार किया है क्योंकि उस देश को निर्यात उसी समय में किए गए हैं जब भारत को किए गए थे। पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध 2 की धारा 6(1) के अनुसार, पाटन मार्जिन निकालते समय, निर्दिष्ट प्राधिकारी निर्यात कीमत और सामान्य मूल्य के बीच उचित तुलना करेंगे। तुलना व्यापार के एक स्तर पर सामान्यतः व्यापार के उसी स्तर पर की गई बिक्रियों के सम्बंध में कारखाना गत स्तर पर सामान्यतः जहां तक संभव हो एक ही समय में की गई बिक्रियों के संबंध में की जाएगी। प्राधिकारी ने नोट किया था कि ईरान देश को की गई बिक्रियां उसी समय में की गई थीं जब उन्होंने भारत में वस्तु का नौवहन किया था। प्राधिकारी ने ईरान के उपर्युक्त तीसरे देश के रूप में भी लिया था क्योंकि इसके विकास और आर्थिक मानदण्ड निर्यात देश के अधिक समरूप है। प्राधिकारी ने निर्धारण पैकिंग हेतु \*\*\*\* देश अ.डा./कि.ग्रा. अंतर्देशीय भाड़े के लिए \*\*\*\* अ.डा./कि.ग्रा., विदेशी भाड़े के लिए \*\*\*\* अ.डा./कि.ग्रा., विदेशी बीमे के लिए \*\*\*\* अ.डा./कि.ग्रा. कटौती के पश्चात् \*\*\*\* देश को निर्यात के लिए \*\*\*\* अ.डा./कि.ग्रा. किया है।

### निर्यात कीमत

निर्यात कीमत ने भारत को \*\*\*\* अ.डा. के कुल मूल्य का \*\*\*\* कि.ग्रा. पी एच पी जी बेस निर्यात किया है। उन्होंने निर्यातक की प्रश्नावली के अपने प्रत्युत्तर में भारत को की गई निर्यात बिक्रियों के सौदाबार ब्यौरे दिए हैं। तदनुसार जांच की अवधि के दौरान पी एच पी जी की भारत औसत निर्यात कीमत \*\*\*\* अ.डा./प्रति कि.ग्रा. बनती है। कमीशन तथा भाड़े के संबंध में भारत को निर्यातों के लिए इस फर्म के निर्यात आंकड़ों का सत्यापन करने के पश्चात् प्राधिकारी अंतर्देशीय भाड़े पर \*\*\*\* अ.डा./प्रति कि.ग्रा., पैकिंग \*\*\*\* अ.डा./कि.ग्रा., अंतर्देशीय बीमा \*\*\*\* अ.डा./कि.ग्रा., विदेशी भाड़ा \*\*\*\* अ.डा./कि.ग्रा., विदेशी बीमा \*\*\*\* अ.डा./कि.ग्रा., पत्तन प्रभार \*\*\*\* अ.डा./कि.ग्रा., कलीएरेन्स तथा हैंडलिंग प्रभार \*\*\*\* अ.डा./कि.ग्रा., के कारण समायोजन के पश्चात् भारत को निर्यात बिक्री के लिए भारित कारखानागत कीमत \*\*\*\* अ.डा./कि.ग्रा. निर्धारित की है।

पाटन मार्जिन, भारित औसत सामान्य मूल्य के साथ भारित औसत निर्यात कीमत की तुलना के आधार पर निर्धारित किया गया है। स्पेन के मै. डी.एस.एम. डैरिटल एस.ए. के मामले में पाटन मार्जिन प्राधिकारी द्वारा निर्यात कीमत पर \*\*\*\* प्रति कि.ग्रा. अथवा 1.21% मूल्यांकित किया गया है।

### मैसर्स रिकार्डेटी, इटली

17. मैसर्स रिकार्डेटी ने केवल सामान्य निवेदन किया है तथा उनके एवं याचिकाकर्ता द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली प्रौद्योगिकी पर टिप्पणी की है। उन्होंने निर्यातक प्रश्नावली में निर्धारित तरीके एवं रूप में आंकड़े/सूचना प्रस्तुत नहीं की तथा निर्यातक प्रश्नावली में उल्लिखित विभिन्न परिशिष्टों से संबंधित आंकड़े भी प्रस्तुत नहीं किए। इसलिए प्राधिकारी ने निर्यातक को असहयोगी माना है। चूंकि संबद्ध वस्तुओं का घरेलू बिक्री कीमत ढांचा, यूरोपीय संघ में इसकी उत्पादन लागत तथा प्रश्नावली के अनुसार अन्य सूचनाओं के बारे में कोई सूचना/आंकड़े नहीं दिए गए, इसलिए यह संभव नहीं है कि पाटनरोधी नियमावली तथा डब्ल्यूटी ओ में निहित प्रावधानों के अनुसार व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में सामान्य मूल्य का निर्धारण किया जाए। इसलिए प्राधिकारी सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए उपलब्ध सर्वोच्च सूचना पर निर्भर रहने के लिए बाध्य है। याचिकाकर्ता ने यूरोपीय संघ के संबंध में परिकलित उत्पादन लागत के आधार पर सामान्य मूल्य का दावा किया है। उत्पादन लागत तथा घरेलू बिक्री सौदों के बारे में आंकड़ों की अनुपस्थिति में प्राधिकारी ने इसी पर विचार किया। उपरोक्त नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य का निर्धारण किया।

मैसर्स रिकार्डेटी, इटली द्वारा इस प्रकार से निर्धारित सामान्य मूल्य \*\*\*\* अमेरिकी डालर प्रति कि.ग्रा. है।

जहां तक मैसर्स रिकार्डेटी के लिए निर्यात कीमत निर्धारित करने का मामला है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि यूरोपीय संघ से जांच अवधि के दौरान \*\*\*\* अमेरिकी डालर प्रति कि.ग्रा. की यूनिट कीमत पर \*\*\*\* अमेरिकी डालर का \*\*\*\* मी. टन संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया गया। अंतर्देशीय भाड़े, बीमा समुद्री भाड़ा, कमीशन तथा समुद्री बीमा, जैसाकि मैसर्स डेरीटल, डी एस एम स्पेन के मामले में किया गया था, के कारण समायोजन के पश्चात् प्राधिकारी ने \*\*\*\* अमेरिकी डालर/कि.ग्रा. पर भारित कारखानागत निर्यात कीमत का निर्धारण किया है।

इसलिए रिकार्डेटी के मामले में प्राधिकारी द्वारा आंकलित पाटन मार्जिन \*\*\*\* अमेरिकी डालर प्रति कि.ग्रा. या निर्यात कीमत का 78.48% है।

### यूरोपीय संघ के अन्य निर्यातक :

18. उपरोक्त नियमावली के अनुसार प्राधिकारी ने यूरोपीय संघ के निर्यातकों को यह अवसर प्रदान किया कि वे जांच से संबंधित सूचना प्रस्तुत करें तथा, यदि कोई हो तो, उस पर अपनी टिप्पणी दें। प्राधिकारी नोट करते हैं कि ई.यू. से उपर्युक्त के अलावा किसी भी निर्यात ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया और प्रश्नावली के अनुसार संबद्ध वस्तु की बिक्री कीमत ढांचे, ई.यू. में इसकी उत्पादन लागत और अन्य संबंधित सूचना नहीं दी है। सूचना/

आंकड़ों की अनुपस्थिति में प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए उपलब्ध सर्वोच्च सूचना के सहरे कार्रवाई की है। याचिकाकर्ता ने परिकलित उत्पादन लागत के आधार पर ही यूरोपीय संघ के लिए सामान्य मूल्य का दावा किया है। उत्पादन लागत तथा घरेलू बिक्री सौदों की आंकड़ों की अनुपस्थिति में प्राधिकारी ने इसी पर विचार किया है।

तदनुसार नियम 6(8) के अनुसार प्राधिकारी ने यथोचित समायोजनों के साथ उपलब्ध तथ्यों के आधार पर सामान्य मूल्य का परिकलन किया है। यूरोपीय संघ से अन्य निर्यातों के लिए इस प्रकार से निर्धारित सामान्य मूल्य \*\*\*\* अमेरिकी डालर/कि.ग्रा. है।

प्राधिकारी ने मैसर्स रेकार्डेटी, इटली के मामले की तरह अन्य निर्यातकों के लिए कारखाना द्वारा स्तर पर निर्यात कीमत का आंकलन किया है इसलिए मैसर्स डी एस एम डेरेटिल, स्पेन की तरह सभी समायोजनों के पश्चात् कारखाना द्वारा पर भारित औसत निर्यात कीमत \*\*\*\* अमेरिकी डालर/कि.ग्रा. है।

इसलिए प्राधिकारी द्वारा यूरोपीय संघ से पी एच पी जी बैस के अन्य निर्यातकों/असहयोग के मामले में \*\*\*\* अमेरिकी डालर प्रति कि.ग्रा. या निर्यात की कीमत का 78.48% पाठन मार्जिन का आंकलन किया गया है।

निर्यातक देश/क्षेत्र	सामान्य मूल्य	निर्यात मूल्य	पाठन मार्जिन
			प्रतिशत निर्यात मूल्य
डी एस एम डेरेटिल, स्पेन	****	****	1.21
रिकोडिटी, इटली	****	****	78.48
अन्य निर्यातक यूरोपीय संघ से	****	****	78.46

#### ज. क्षति से संबंधित मामले

##### निर्यातक के विवार, मैसर्स डी एस एम डेरेटिल, स्पेन

19. अन्य बातों के साथ-साथ धारा 9 खं में प्रावधान है कि डब्ल्यू टी ओ के सदस्य देश से भारत में किसी वस्तु के आयात पर तब तक पाठनरोधी शुल्क न लगाया जाए जब तक कि इस बात का निर्धारण न हो जाए कि भारत में ऐसे वस्तु के आयात से भारत में स्थापित किसी उद्योग को वास्तविक क्षति का खतरा है या ऐसे वस्तु के आयात से भारत में स्थापित उद्योगों के विकास में बाधा डालेंगे। यहाँ यह बताना महत्वपूर्ण होगा कि धारा 9 खं तीन परस्पर विशिष्ट क्षति निर्धारणों के बारे में बताती है। वे हैं :

- (क) वास्तविक पर्याप्त क्षति; या
- (ख) वास्तविक क्षति का खंतरा; या
- (ग) भारत में उद्योग की स्थापना के विकास में वास्तविक बाधा।

जांच अवधि के दौरान वास्तविक क्षति की परिभाषा के अनुसार वास्तविक क्षति के खतरे या विकास में बाधा को अलग रखा गया है। जांच अवधि के दौरान वास्तविक क्षति की अनुपस्थिति में पाठनरोधी शुल्क लगाया जा सकता है वह भी तब जबकि भविष्य में वास्तविक क्षति के खतरे के बारे में ज्ञात हो जाता है। वास्तविक बाधा में न तो विद्यमान वास्तविक क्षति दी और न भविष्य में होने वाली क्षति का खतरा शामिल है। यह कार्य ऐसी स्थिति में हुआ है जिसमें समान वस्तुओं का विनिर्माण करने वाले उद्योगों को स्थापित करने की कोशिश की जा रही है तथा कथित प्रतिट आयातों के कारण उनकी कोशिशों में वास्तविक विघ्न आ रहे हैं जांच परिणामों में देखा जा सकता है, कि ऐसा कोई स्पष्ट सूचक नहीं है जिससे यह पता चले कि इस जांच विद्यमान तीन में से कौन सा पहलू पाया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, उन सभी 15 तथ्यों, जिनकी क्षति के प्रयोजनार्थ अवश्य ही जांच की जानी चाहिए, का भी मूल्यांकन नहीं किया गया।

कारणात्मक संबंध की व्यवस्था बनावटी है। प्रारंभिक जांच परिणामों के पैरा 24(ए) पता चलता है कि सितम्बर, 2001 में यूरोपीय संघ से औसत आयात कीमत 11.816 अमेरिकी डालर प्रति कि. ग्रा. है। जुलाई, 2001 में डी एस एम डेरेटिल द्वारा निर्यात उस कीमत पर किए गए जो पैरा 24(क) में बताई गई कीमतों से कहर्वे अधिक थे। पैरा 24(ड) सारणी से पता चलता है कि घरेलू उद्योग के लिए जांच अवधि के दौरान निवल वसूलियों में कमी आई। यह देखा जाता है कि निवल वसूली जो कि जून, 2001 में लगभग 100 थी सितम्बर, 2001 में घटकर लगभग 80 हो गई। यह नोट करना महत्वपूर्ण होगा कि कीमतों में कमी आई जो जुलाई 2001 में घटकर 89.47 तथा अगस्त 2001 में 91.42 हो गई जबकि यूरोपीय संघ से इन महीनों

के दौरान इस उत्पादन के लिए कोई आयात नहीं हुए। यह दर्शाता है कि जुलाई तथा अगस्त में आई कीमतों में कमी यूरोपीय संघ से हुए आयातों से प्रभावित नहीं थी। यदि यह ऐसा था तो यह ज्ञात नहीं कि किस आधार पर अगस्त 2001 से सितम्बर, 2001 में आई कीमतों में कमी यूरोपीय संघ द्वारा बताई गई थी। हम यह निवेदन करते हैं कि निवल बिक्री वसूलियों में आई कमी यूरोपीय संघ विशेषतः डी एस एम डेरेटिल द्वारा नहीं की गई।

प्रारंभिक जांच परिणामों से पता चलता है कि वर्तमान जांच में डी एस एम डेरेटिल के अतिरिक्त अन्य सभी निर्यातकों के लिए संदर्भ कीमत 21.81 अमेरिकी डालर प्रति कि.ग्रा. है। यह फिर से बताता है कि घरेलू उद्योग के लिए एन आई पी 21.81 अमेरिकी डालर है। इन दोनों आंकड़ों की तुलना बताती है कि 1 अप्रैल 2001 से 20 सितम्बर 2001 के लिए लागत+लाभ 24.83 अमेरिकी डालर है जबकि 1 अप्रैल 2001 से 31 दिसम्बर 2001 नौ माह की अवधि के लिए यह 21.81 अमेरिकी डालर है। एन आई पी में 12% की गिरावट आई है। चूंकि 3 महीने का एन आई पी तथा 6 महीने के एन आई पी (24.83 अमेरिकी डालर) औसत 21.81 अमेरिकी डालर होगा इसलिए यह स्वतः सिद्ध है कि तीन महीनों की अवधि के लिए एन आई पी (अक्टूबर-दिसम्बर 2001) 21.81 अमेरिकी डालर से बहुत कम होगी व्यंजेकि 21.81 अ. डा. का भारित औसत 9 महीनों की अवधि का चुना जो कि वाणिज्यिक उत्पादन के प्रारंभ के साथ ही पड़ता है को निम्न क्षमता उपयोग तथा उच्च प्रारंभिक लागत का होना पड़ेगा जिससे उच्च एन आई पी हुई है। एन आई पी के निर्धारण को एक बार फिर से देखने की आवश्यकता है ताकि प्रारंभिक प्रक्रिया से जुड़ी असामान्य/शुरू करने की लागत के लिए समायोजन किया जा सके। ऐसा लगता है कि घरेलू उद्योग पाटनरोधी कार्रवाईयों का अनुचित लाभ उठा रहे हैं ताकि वे अपने आपको लगाए गए किसी भी नए उद्योग को शुरूआती दौर में होने वाली सामान्य परेशानियों से बच सके।

हम प्राधिकारी से एन आई पी को तिमाही आधार पर निर्धारित करने के अनुरोध करते हैं तथा डी एस एम डेरेटिल से आयातों के पहुंच मूल्य की तुलना अक्टूबर-दिसम्बर 2001 तिमाही के लिए एन आई पी से करेंगे। वास्तव में वर्तमान मापदण्ड में ही निर्दिष्ट प्राधिकारी ने घरेलू बिक्री वसूली पर मासिक आधार पर विचार किया है। निर्दिष्ट प्राधिकारी को उत्पादन लागत पर मासिक आधार पर तथा एन आई पी पर कम से कम तिमाही आधार पर विचार करना चाहिए।

इस अवधि के लिए घरेलू उद्योग के लिए एन आई पी 15.77 अमेरिकी डालर प्रति कि. ग्रा. के लगभग थी जबकि यूरोपीय संघ से पहुंच मूल्य एन आई पी से कहीं अधिक था। वास्तव में, डी एस एम डेरेटिल से निर्यातों का पहुंच मूल्य एन आई पी से 25% अधिक था। इसलिए डी एस एम डेरेटिल द्वारा कीमत न्यूनीकरण नहीं किया गया।

यह भी आवश्यक है कि न्यूनीकरण का निर्धारण व्यक्तिगत निर्यातकों के संदर्भ में किया जाए न कि संपूर्ण रूप से डी एस एम डेरेटिल का पहुंच मूल्य निर्दिष्ट प्राधिकारी के पास उपलब्ध है। अक्टूबर-दिसम्बर की अवधि के लिए भी एन आई पी उपलब्ध है। यह स्पष्टतः बताता है कि डी एस एम डेरेटिल का पहुंच मूल्य एन आई पी से अधिक है।

20. अंत में, डी एस एम डेरेटिल की ओर से हम निवेदन करते हैं कि :

- (i) घरेलू उद्योग की टिप्पणियां केवल अव्यवहारिक आक्षेप तथा मात्र कल्पना हैं जिन्हें पूरी तरह से अनदेखा करना चाहिए।
- (ii) डी एस एम डेरेटिल की निर्यात कीमतों से घरेलू उद्योग को कोई वास्तविक क्षति नहीं हुई, तथा
- (iii) क्षति तथा पाटन मार्जिन दोनों की अनुपस्थिति के कारण जांच को समाप्त कर देना चाहिए।

#### ट. घरेलू उद्योग के दिच्चार

21. चीन और सिंगापुर से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को पहले क्षति हो रही थी। निर्दिष्ट प्राधिकारी ने इन देशों से आयातों पर पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश की थी जिसे भारत सरकार द्वारा लगा दिया गया है। अतः घरेलू उद्योग को क्षति की जांच विद्यमान पाटनरोधी शुल्क को ध्यान में रखकर किए जाने की आवश्यकता है। पाटित आयातों से घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति का खतरा है। यह कहना भी प्रासंगिक होगा कि याचिकाकर्ता ने वाणिज्यिक उत्पाद 1 अप्रैल से शुरू किया है इसलिए घरेलू उद्योग की क्षति से संबंधित सभी मानदंडों को घरेलू उद्योग के इस छोटे वाणिज्यिक इतिहास की ध्यान में रखकर देखा जाना चाहिए।

संबंध देशों से आयातों में संपूर्ण रूप से वृद्धि हुई है। यूरोपीय संघ से आयातों के हिस्से में उल्लेखनीय रूप से वृद्धि हुई है। यूरोपीय संघ से आयात जो अगस्त 2001 तक शून्य था अब बड़ी मात्रा में आने शुरू हो गये हैं। यह इस तथ्य के कारण है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने अक्टूबर 2001 में चीन और सिंगापुर से संबंध वस्तुओं की जांच आरंभ की थी। यह इस तथ्य के बावजूद है कि घरेलू उद्योग ने अपना वाणिज्यिक उत्पादन अभी शुरू किया था। संबंध देशों से निर्यातकों ने कीमतों में कटौती की है और भारत में बाजार हिस्से में वृद्धि के लिए उत्साहित किया और इस प्रकार घरेलू उद्योग के अस्तित्व की प्रारंभिक स्तर पर ही वास्तविक बाधा पहुंचाई। घरेलू उद्योग अपनी क्षमता के प्रति आशावादी नहीं हो सका जो अन्यथा पाटित आयातों की अनुपस्थिति में प्राप्त की जा सकती है। मांग में वृद्धि के बावजूद घरेलू उद्योग की बिक्री में वृद्धि नहीं हो पाई। परिवर्तित स्थोत्रों से उपभोक्ताओं को पाटित आयातों की उपलब्धता के कारण गिरावट आई है। संबंध देशों के निर्यातकों ने कीमतों में भारी कमी की है। पाटित कीमतों पर संबद्ध वस्तु के आयात के कारण घरेलू उद्योग की बिक्री में कमी हुई है। घरेलू उद्योग की अपने कर्मचारियों की बनाए रखने की प्रवृत्ति है। इसके अतिरिक्त याचिकाकर्ता

ने संबद्ध वस्तुओं के लिए नई सुविधाएं स्थापित की हैं परन्तु यदि वर्तमान प्रवृत्ति जारी रही तो घरेलू उद्योग को रोजगार स्तर में कमी करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। निर्यात के पहुंच मूल्य के अनुरूप पहले से कम बिक्री कीमतों की और कम किया है जिसके परिणामस्वरूप हानि हुई है। घरेलू उद्योग उस कीमत पर भी बिक्री नहीं कर पा रहा जिससे लगाई गई पूंजी पर उचित वसूली तो छोड़े अपनी उत्पादन लागत भी नहीं निकाल पा रहा है। अतः हम देखते हैं कि घरेलू उद्योग को इस प्रकार वास्तविक क्षति हुई है। इसके अतिरिक्त घरेलू उद्योग को पाटित आयातों के कारण वास्तविक क्षति का खतरा है। इसके साथ यह नोट करना उतना ही महत्वपूर्ण है कि घरेलू उद्योग ने हाल में ही अपना वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया है अतः घरेलू उद्योग स्थापित होने में बाधा हो रही है।

### प्राधिकारी द्वारा जांच :

#### ठ. क्षति :

22. उपरोक्त नियम 11, अनुबंध-II के अंतर्गत जब क्षति के बारे में निष्कर्ष निकाला जाता है तो ऐसे निष्कर्ष में “..... पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में मूल्यों पर उनका प्रभाव ऐसे वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयातों के परिणामकारी प्रभावी समेत सभी संगत तथ्यों पर विचार करते हुए घरेलू उद्योग को हुई क्षति का निर्धारण शामिल होगा। मूल्यों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते समय इस बात की जांच करनी आवश्यक समझी जाती है कि क्या भारत में समान वस्तु के मूल्य की तुलना में पाटित आयातों से मूल्यों में पर्याप्त गिरावट आई है अथवा क्या अन्यथा ऐसे आयातों का उद्देश्य मूल्यों को काफी हद तक रिश्वर रखना है अथवा मूल्य वृद्धि को रोकना है जो अन्यथा काफी हद तक हो गई होती।”

भारत में घरेलू उद्योग पर प्रभाव की जांच करने के लिए प्राधिकारी ने क्षमता उपयोग, उत्पादन, बिक्री, निवल बिक्री प्राप्ति, लाभप्रदता इत्यादि जैसे अन्य संकेतों पर भी विचार किया जो उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालते हैं। प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को क्षति दर्शाने वाले विभिन्न मापदंडों को ध्यान में रखा जो निम्नलिखित हैं :—

#### ( क ) आयातों की मात्रा एवं निर्यात कीमत

संबद्ध वस्तु के आयातों की मात्रा से संबंधित में सूचना सीमाशुल्क दैनिक सूचियों से संकलित आंकड़ों पर आधारित है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जांच अवधि के दौरान संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों की मात्रा में 2002-01 की तुलना में 562.5% की वृद्धि हुई है। इसके अलावा जांच अवधि के दौरान संबद्ध देशों से औसत निर्यात कीमत में भी वर्ष 2000-01 की तुलना में गिरावट आई है।

#### यूरोपीय संघ से आयात:

#### सारणी

अवधि	मात्रा (मी. टन)	मूल्य (रु./लाख)	औसत कीमत दर अ.डा. मी. टन	%आयात का हिस्सा
1998-99	129	18505553	14259	18.82
1999-00	128	1861378	14486	13.11
2000-01	24	169.01	14907.85	2.38
(अप्रैल-दिसम्बर) 2001	135	749.49	11577.14	12.12
(2001-02)	180	999.33	11577.14	12.12

#### यूरोपीय संघ से महावार आयात

अवधि 2001	मात्रा (कि.ग्रा.)	मूल्य (लाख रुपयों)	दर/यूएस डा.मी. टन
अप्रैल	शून्य	शून्य	शून्य
मई	शून्य	शून्य	शून्य
जून	शून्य	शून्य	शून्य
जुलाई	शून्य	शून्य	शून्य
अगस्त	शून्य	शून्य	शून्य
सितम्बर	45,000	251.79	11816.90
अक्टूबर	शून्य	शून्य	शून्य
नवम्बर	60,000	332.99	11502.15
दिसम्बर	30,000	164.71	11367.47

**( ख ) भारतीय उत्पादकों और संबद्ध देशों के आयातकों के बाजार हिस्से में परिवर्तन**

प्राधिकारी यह पाते हैं कि मैं डॉ ओ एल भारत में संबद्ध वस्तु के विनिर्माण में नया प्रवेशकर्ता है और संबद्ध देशों के निर्यातकों ने भारत में संबद्ध वस्तु का पाटन बढ़ा दिया है ताकि वह सुनिश्चित हो सके कि घरेलू उद्योग का कोई बाजार हिस्सा न हो तथा उद्योग स्थापना आरंभिक में ही बाधित हो जाए।

**( ग ) याचिकाकर्ता का उत्पादन एवं क्षमता उपयोग**

घरेलू उद्योग ने संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन जांच अवधि के दौरान ही आरंभ किया है तथा जांच अवधि के दौरान अपनी वर्तमान स्थापित क्षमता को केवल \*\*\*\*% का उपयोग किया है। देश में मांग को ध्यान में रखते हुए यह घरेलू उद्योग द्वारा जो उपयोग किया जा सकता था उससे काफी कम है।

**( घ ) बाजार हिस्से की नगण्य वृद्धि**

घरेलू उद्योग आरंभिक स्थिति में है, अतः पिछला रूज्ञान उपलब्ध नहीं हैं लेकिन संबद्ध देशों से पाठित आयातों के कारण देश में संबद्ध वस्तु की मांग अधिक होने के बावजूद घरेलू उद्योग अपनी बिक्री मात्रा को बढ़ाने में असमर्थ है।

**( ङ ) बिक्री कीमत में कमी, कीमत न्यूनीकरण, कीमत में कटौती, कीमत में गिरावट अथवा कीमत ह्रास**

घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत पर पाठित आयातों के प्रभाव का विश्लेषण करने के लिए संबद्ध वस्तु की मासिक बिक्री प्राप्ति का निम्नानुसार विश्लेषण किया गया है :—

अवधि	मात्रा बिक्री (किग्रा.)	निवल बिक्री प्राप्ति (रु./किग्रा.)
अप्रैल 2001	****	100
मई 2001	****	100
जून 2001	****	100
जुलाई 2001	****	89.47
अगस्त 2001	****	91.42
सितम्बर 2001	****	79.06
अक्टूबर 2001	****	75.61
नवम्बर	****	75.72
दिसम्बर	****	78.34

सूचीबद्ध आकड़ों को अप्रैल 2001 में 100 के रूप में माना गया है।

उपर्युक्त सारणी से यह पता चलता है कि जांच अवधित के दौरान मासिक औसत बिक्री प्राप्ति अप्रैल 2001 के दौरान \*\*\*रु./किग्रा. से घटकर दिसम्बर 2001 के दौरान \*\*\*रु./किग्रा. रह गई है जिससे जांच अवधि के भीतर ही गिरावट प्रदर्शित होती है। यह मुख्यतः घरेलू उद्योग द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने के बाद निर्यातकों द्वारा औसत कीमत में की गई कमी के कारण हुआ है।

**( च ) गवाई गई संविदाओं अथवा कम होती हुई बिक्रियों का साक्ष्य**

यह देखा गया है कि निर्यातकों द्वारा निर्यात कीमत में तेजी से कमी किए जाने के कारण घरेलू उद्योग उस कीमत पर संविदाएं आदेश नहीं प्राप्त कर सका जिससे लगाई गई पूँजी पर उचित आय की प्राप्ति तो दूर उत्पादन लागत भी प्राप्त हो सके। याचिकाकर्ता संबद्ध वस्तु को काफी घाटे पर ही बेच सका।

**( छ ) रोजगार**

घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि चूंकि उद्योग अपने आरंभिक चरण में है इसलिए अनुचित व्यापार प्रक्रिया से उसका बचाव करना महत्वपूर्ण तथा अत्यावश्यक है अन्यथा कार्यरत कर्मचारियों को अपना रोजगार गवाना पड़ेगा।

**( ज ) लाभप्रदता**

यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग ने संबद्ध वस्तु की बिक्री निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत कीमतों के बराबर कीमतों पर बेचने की कोशिश की जिससे उसे भारी घाटा हुआ।

वर्तमान याचिका पाटित आयातों के प्रभाव से संबंधित है जोकि उद्योग की स्थापना में वास्तविक बाधा उत्पन्न कर रहा है। चूंकि याचिकाकर्ता अपने उत्पादन का निपटान भारतीय बाजार में ही करने की कोशिश कर रहा है तथा संबद्ध देशों से आयात घरेलू उद्योग के उत्पादन के वाणिज्यिकरण को रोक रहे हैं, इसलिए आयात उद्योग की स्थापना में वास्तविक बाधा उत्पन्न कर रहे हैं यद्यपि नवस्थापित उद्योग अर्थात् मै. दौराला अरणीनिक्स लि. ने हाल ही में उत्पादन आरंभ किया है परन्तु उद्योग की अभी बाजार में अपना स्थान बनाना है। घरेलू उद्योग क्षमता उपयोग के संतोषजनक स्तर को पाने में तथा बाजार में अपना स्थान बनाने में असमर्थ हैं क्योंकि आरंभिक चरण में ही घरेलू उद्योग को संबद्ध देशों से पाटित कीमतों पर हुए आयातों पर हुए आयातों द्वारा वास्तविक बाधा उत्पन्न होने का खतरा पैदा हो रहा है।

### कीमत कटौती तथा बिक्री कीमत में कमी

जांच अवधि के दौरान कीमत में कटौती			
देश/क्षेत्र	निवल बिक्री कीमत याचिकाकर्ता	संबद्ध देश में पहुंच कीमत	कीमत में कटौती
यूरोप संघ			
डीएसएम डेरेटिल स्पेन	****	****	(—) ****
रिकार्डिंग, इटली	****	****	****
जांच अवधि के दौरान बिक्री कीमत में कमी			
देश	याचिकाकर्ता की क्षतिरहित कीमत	संबद्ध देश से पहुंच कीमत	बिक्री की कीमत में कटौती
यूरोपीय संघ			
डीएसएम डेरेटिल स्पेन	****	****	****
रिकार्डिंग, इटली	****	****	****

कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते हुए, यह जांच करना आवश्यक समझा जाता है कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत के साथ तुलना में पाटित आयातों द्वारा कीमत में पर्याप्त कटौती हुई है या क्या इस प्रकार के आयातों का प्रभाव अन्यथा कीमतों को उल्लेखनीय स्तर तक कम करना है। प्राधिकारी ने जांच अवधि के दौरान सम्बद्ध देशों से सम्बद्ध वस्तुओं के आयातों के पहुंच मूल्य को तुलना निवल बिक्री वसूली से की है तथा पाया कि सम्बद्ध देश/क्षेत्र से पाटित आयातों द्वारा कीमतों में भारी कटौती हुई है (डी एस एम डेरेटिल, स्पेन को छोड़कर) आयातों का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग की निवल बिक्री वसूली से कम पाया गया है।

प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता के इस दावे की भी जांच की कि घरेलू उद्योग को हानियों के कारण क्षति हो रही है प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति का मूल्यांकन करने के लिए कीमत में कटौती एक महत्वपूर्ण संकेतक है। प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद के लिए क्षति रहित कीमत निर्धारित की है तथा कीमत कटौती के स्तर का पता लगाने के लिए उसकी तुलना पहुंच मूल्य से की है। विश्लेषण से पता चलता है कि घरेलू उद्योग को क्षति के कारण कीमत में भारी कटौती हुई है। आयातों का घरेलू बाजार में कीमतों पर भारी न्यूनीकरण/हास का प्रभाव पड़ा है क्योंकि पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग अपनी बिक्री कीमत में वृद्धि नहीं कर सका।

### बिक्री कीमती/लाभ प्रदत्ता

24. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की बिक्री कीमतें, उस कीमत से उल्लेखनीय रूप से कम है जिस कीमत पर घरेलू उद्योग अपनी उत्पादन लागत की वसूली कर सके और उचित प्रतिलाभ मिल सके। इस प्रकार पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग उचित कीमत वसूली हेतु न्याय संगत कीमत वृद्धि नहीं कर पा रहा। कम बिक्री कीमतों के कारण उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है जिसके परिणामस्वरूप उत्पादन लागत की वसूली नहीं हो पा रही तथा इसके कारण वित्तीय हानि हुई।

प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के इस दावे की भी जांच की कि वह वास्तविक क्षति के अतिरिक्त वास्तविक क्षति के खतरे का भी सामना कर रहा है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी करार के 3.7 के अनुसार वास्तविक क्षति के खतरे का निर्धारण लक्ष्यों के आधार पर किया जाएगा न कि आरोप, अनुमान और संभाव्यता के आधार पर। परिस्थितियों में परिवर्तन जिससे ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है जिसमें पाटन से क्षति होगी जिसे स्पष्ट: देखा जा सकता है। वास्तविक क्षति के खतरे की विद्यमानता के निर्धारण के लिए प्राधिकारी ने पाटनरोधी करार के पैरा 3.7(i)-(iv) तथा सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के अंतर्गत किए गए पाटनरोधी नियमाबली के अनुबंध-II के अनुसार रखे गए तथ्यों का विश्लेषण किया है।

पिछले वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान सम्बद्ध देश से घरेलू बाजार में पाटित आयातों की वृद्धि दर में उल्लेखनीय रूप से वृद्धि हुई है।

याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि यूरोपीय संघ के समक्ष सम्बद्ध वस्तुओं के निर्माण हेतु बड़ी मात्रा में अप्रयुक्त क्षमता है। हालांकि यूरोपीय संघ के मुख्य निर्यातक में रिकाडेडी, इटली जिसने जांच अवधि के दौरान सम्बद्ध वस्तुओं का 90% हिस्सा निर्यात किया है तथा जिसने इस याचिका का प्रत्युत्तर दिया है, उन्होंने निर्यातक प्रश्नावली में, अपने संयंत्र की क्षमता और अपने तैयार माल की भण्डार सूची के बारे में उल्लेख नहीं किया है।

उपर्युक्त जांच परिणामों के आधार पर प्राधिकारी नोट करते हैं कि याचिकाकर्ता को पहले हुई वास्तविक क्षति के अतिरिक्त आगे क्षति का खतरा है।

### इ कारणात्मक संबंध

25. यह निर्धारण करते समय कि क्या घरेलू उद्योग को पाटित आयातों से क्षति पहुंची थी, प्राधिकारी ने निम्नलिखित तथ्यों को ध्यान में रखा :—

- (i) यूरोपीय संघ से पाटित कीमतों पर संबद्ध वस्तु के पर्याप्त आयातों से घरेलू उद्योग को अपनी बिक्री कीमत अलाभकारी स्तर तक घटाने के लिए विवश होना पड़ा जिसके परिणामस्वरूप भारतीय बाजार में कीमत कटौती की स्थिति पैदा हुई है।
- (ii) यूरोपीय संघ से हुए आयातों से भारतीय बाजार में उत्पाद की कीमतें इस हद तक कम हो गई कि घरेलू उद्योग अपने उत्पादन की पूरी कीमत वसूलने और भारत में संबद्ध वस्तु की बिक्री से यथोचित लाभ प्राप्त करने से वंचित हो गया।

प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच अवधि के दौरान यूरोपीय संघ से संबद्ध वस्तुओं के आयात इस देश में कुल आयातों का 21.2% है। यह भी नोट किया गया कि जांच अवधि के दौरान सम्बद्ध क्षेत्र से पाटित आयात, यूरोपीय संघ से कुल आयात का 90% से अधिक है। पिछले वर्ष के दौरान सम्बद्ध देश/क्षेत्र से आयात में कुल आयातों का 2% वृद्धि हुई थी जबकि जांच अवधि के दौरान कुल आयातों में 21% की वृद्धि हुई। इस प्रकार मात्रा में क्षति स्पष्टतः दिखाई देती है। कीमत प्रभाव की जांच करते समय प्राधिकारी नोट करते हैं कि सम्बद्ध देश/क्षेत्र से कम कीमत पर आयातों के कारण याचिकाकर्ता को कम कीमतों पर बिक्री के लिए मजबूर होना पड़ा तथा जांच अवधि के दौरान सम्बद्ध वस्तुओं की बिक्री पर हानि उठानी पड़ी। सम्बद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग घरेलू बाजार में उचित लाभकर बिक्री कीमत वसूल नहीं कर पा रहा। पाटित आयात कीमतों के समकक्ष अपनी कीमतें रखने के कारण घरेलू उद्योग को अपनी क्षति रहित कीमत से कम पर बेचने के लिए बाध्य होना पड़ा जिसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग वसूली नहीं कर सका।

पिछले वर्षों की तुलना में जांच अवधि के दौरान देशों से आयात बहुत कम है तथा इन देशों की कीमतें बहुत अधिक हैं। प्राधिकारी को मांग में कमी, खपत की प्रणाली में परिवर्तन, व्यापार प्रतिबंध प्रणाली और विदेशी तथा घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा के कोई साक्ष्य नहीं मिलते। यह भी नोट किया गया कि प्रौद्योगिकी में विकास घरेलू उद्योग को क्षति का कारण नहीं है।

सम्बद्ध वस्तुओं के लिए पहुंच मूल्य का निर्धारण भारित औसत सी आई एफ निर्यात कीमत, सीमाशुल्क के उपयुक्त स्तर [धारा 3, 3(क), 8ख, 9, 9(क) और उत्तराई प्रभार लिए 1% को छोड़कर] को जोड़ कर किया गया है।

घरेलू उद्योग के लिए समान वस्तुओं हेतु क्षति कीमत का निर्धारण करते समय प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के लिए इष्टतम उत्पादन लागत निर्धारित करने के लिए सम्बद्ध वस्तुओं की वास्तविक उत्पादन लागत का प्रयोग किया है, जिसमें नियामक उचित खपत मानदण्ड और जांच अवधि के दौरान सम्बद्ध वस्तुओं के उत्पादन हेतु उपयुक्त कच्चे माल की वास्तविक कीमत का ध्यान में रखा जाएगा, क्षति मार्जिन का परिकलन करते समय जांच अवधि के लिए निर्धारित कारखानागत क्षति रहित कीमत की तुलना आयातित वस्तुओं के पहुंच मूल्य से करने का प्रस्ताव किया गया है।

### 26. पाटन मार्जिन तक शुल्क

प्राधिकारी ने पाटन मार्जिन के समकक्ष या उससे कम पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश की है जो यदि लगाया गया तो घरेलू उद्योग की क्षति को समाप्त करेगा।

### द. भारतीय उद्योग का हित

27. पाटनरोधी शुल्क लगाने का उद्देश्य सामान्य तौर पर ऐसे पाटन को समाप्त करना है जिससे भारतीय उद्योग को क्षति हो रही है तथा भारतीय बाजार में ऐसी खुली एवं उचित प्रतिस्पर्धा की पुनः स्थिति लाना है जोकि देश के सामान्य हित में है।

प्राधिकारी यह मानते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से सम्बद्ध वस्तुओं के उपयोग से विनिर्मित उत्पादों के कीमत स्तर प्रभावित होंगे और

परिणामस्वरूप इन उत्पादों की तुलनात्मक प्रतिस्पर्धात्मकता पर प्रभाव पड़ सकता है। किन्तु पाटनरोधी उपायों से भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा कम नहीं होगी। इसके विपरीत पाटनरोधी उपायों को लागू करने से पाटन द्वारा प्राप्त हुए अनुचित लगभग समाप्त होंगे, इसके विपरीत पाटनरोधी उपायों को लागू करने से पाटन द्वारा प्राप्त हुए अनुचित लाभ समाप्त होंगे, भारतीय उद्योग का हास रुकेगा और उपभोक्ताओं के लिए व्यापक विकल्प उपलब्ध रखने में मदद मिलेगी।

प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पाटनरोधी उपायों को लागू करने से यूरोपीय संघ से आयात किसी भी प्रकार कम नहीं होंगे और इस प्रकार उपभोक्ताओं के लिए उत्पाद की उपलब्धता पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

#### ण. निष्कर्ष

28. प्राधिकारी पूर्वोक्त पर विचार करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि :—

- (i) यूरोपीय संघ से भारत को डी (-) पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल ग्लाइसीन बेस का निर्यात उसके सामान्य मूल्य से कम कीमत पर किया गया है;
- (ii) भारतीय उद्योग को इससे वास्तविक क्षति हुई है और इसे आगे और क्षति होने का खतरा है;
- (iii) भारतीय उद्योग को उक्त क्षति के कारण डी (-) पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल ग्लाइसीन बेस के विनिर्माता के लिए नए उद्योग की स्थापना में वास्तविक बाधा उत्पन्न हो रही है;
- (iv) सम्बद्ध क्षेत्र से पाटित आयातों के कारण वास्तविक क्षति और वास्तविक बाधा हुई है;
- (v) प्राधिकारी संबद्ध देशों से डी (-) पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल ग्लाइसीन बेस के सभी आयातों निश्चित रूप से पाटनरोधी शुल्क लगाना आवश्यक समझते हैं ताकि घेरेलू उद्योग की क्षति को दूर किया जा सके। प्राधिकारी द्वारा निर्धारित पाटन मार्जिन उपरोक्त पैराग्राफों में दर्शाया गया है। प्राधिकारी द्वारा निर्धारित पाटन मार्जिन के बराबर या उससे कम पाटन रोधी शुल्क की राशि की सिफारिश करने का प्रस्ताव करते हैं जिसे यदि लगाया जाता है तो उससे घेरेलू उद्योग को हुई क्षति समाप्त हो जाएगी। क्षति की निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ आयातों के पहुंच मूल्य की तुलना जांच अवधि के लिए निर्धारित याचिकाकर्ता कंपनी की क्षति रहित कीमत के साथ करने का प्रस्ताव है;
- (vi) तदनुसार प्राधिकारी सिफारिश करते हैं कि अंतिम निर्धारण होने तक यूरोपीय संघ के मूल के या वहां से निर्यातित सीमा शुल्क शीर्ष 2942 के अंतर्गत आने वाले डी (-) पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल ग्लाइसीन बेस जिसे डी (-) अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल ग्लाइसीन, डी (-) अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल ग्लाइसीन बेस, डी (-) पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल ग्लाइसीन, पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल ग्लाइसीन बेस, डी (-) पी हाइड्रोक्सी फिनाइल ग्लाइसीन बेस, डी (-) पी हाइड्रोक्सी फिनाइल ग्लाइसीन नामों से भी माना जाता है, के सभी आयातों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से अनंतिम पाटन रोधी शुल्क लगाया जाए। नीचे निश्चित देशों के मूल के या वहां से निर्यातित सीमा शुल्क टैरिफ के अध्याय 29 के अंतर्गत आने वाली संबद्ध वस्तु के सभी आयातों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से लगाया जाने वाला पाटनरोधी शुल्क निम्नलिखित सारणी के कालम 3 में उल्लिखित राशि तथा प्रति कि.ग्रा. आयात के पहुंच मूल्य के बीच का अंतर होगा :—

देश/क्षेत्र	उत्पादक/निर्यातक	राशि अ.डा. प्रति कि.ग्रा.
यूरोपीय संघ	डी एस एम डेरेटिल स्पेन	शून्य
	अन्य निर्यातक/उत्पादक	21.60

- (vii) इस उद्देश्य के लिए आयातों का पहुंच मूल्य सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के अधीन सीमाशुल्क विभाग द्वारा यथा निर्धारित आकलन योग्य मूल्य होगा और उसमें सीमाशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 3, 3क, 8ख, 9 तथा 9क के तहत लगाए गए शुल्कों को छोड़कर सभी प्रकार के शुल्क शामिल होंगे।

29. उपर्युक्त के अध्यधीन प्राधिकारी दिनांक 5 जून, 2002 के प्रारंभिक जांच परिणामों की पुष्टि करते हैं।

30. इस आदेश के विरुद्ध अपील पूर्वोक्त अधिनियम के अनुसार सीमाशुल्क, उत्पाद तथा स्वर्ण (नियंत्रण) अपील अधिकरण के समक्ष की जाएगी।

एल. वी. सप्तऋषि, निर्दिष्ट प्राधिकारी

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**  
**(Department of Commerce)**  
**(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 7th March, 2003

**FINAL FINDINGS**

**Subject :—Anti-dumping investigation concerning imports of D (-) Para Hydroxy Phenyl Glycine Base (PHPG Base) originating in or exported from the European Union.**

No. 14/6/2002-DGAD.— Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, thereof;

**A. PROCEDURE:**

2. The procedure described below has been followed:

(i) The Designated Authority (hereinafter referred to as Authority), under the above Rules, received a written petition from M/s Daurala Organics Limited, Daurala, Meerut, U.P. on behalf of the domestic industry, alleging dumping of D (-) Para Hydroxy Phenyl Glycine Base also known as PHPG Base (hereinafter referred to as subject goods) originating in and exported from European Union (hereinafter referred to as subject country / territory) ;

(ii) The Authority notified the Delegation of European Commission in India about the receipt of dumping application made by the petitioner before proceeding to initiate the investigation in accordance with sub-rule (5) of Rule 5 supra;

(iii) The Authority issued a Public Notice dated 8<sup>th</sup> March 2002 published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating anti dumping proceedings concerning imports of D (-) Para Hydroxy Phenyl Glycine

Base falling under Chapter heading 2942 of Schedule I of the Customs Tariff Act.

(iv) The Authority sent questionnaires, to elicit relevant information, to the following known exporters from European Union:

- ❖ M/s. Recordati, Italy
- ❖ M/s DSM Deretil S.A. Spain.

Response has been received from both the exporters.

(v) The Delegation of European Commission in New Delhi was also informed about the initiation of investigation and requested to advise the exporters/producers from their countries to respond to the questionnaire within the prescribed time;

(vi) The questionnaire was sent to the following known users/importers of subject goods:-

- M/s. Aurbindo Pharma Ltd, Hyderabad.
- M/s. Lupin Laboratories Ltd., Mumbai.
- M/s. Kopran Drugs Ltd., Raigad.
- M/s. Surya Pharmaceutical Ltd., Chandigarh.
- M/s. Torrent Gujarat Biotech Ltd, Ahamedabad.
- M/s. Ranbaxy Laboratories Ltd, New Delhi.
- M/s. Tini Pharma Limited, Mumbai.

Response has been received from M/s Torrent Gujarat Biotech Ltd whose submissions are presented in the importer's response. Apart from this, no other users/importers has responded to the questionnaire.

(vii) The Designated Authority issued Preliminary Findings vide notification dated 5<sup>th</sup> June 2002 and forwarded a copy of the preliminary finding to the known exporters and industry associations and gave them an opportunity to make their views known in writing within 40 days from the date of the letter;

(viii) The Authority forwarded a copy of the public notice to the known importers of PHPG base in India and advised them to make their views known in writing within forty days from the date of the letter;

(ix) The Authority provided a copy of the preliminary findings to the Delegation of European Union in with a request that the exporters and

other interested parties may be advised to furnish their views on the preliminary findings;

(x) Additional information regarding injury was sought from the petitioner, which was also received;

(xi) The Authority made available non-confidential version of the evidence presented by various interested parties in the form of a public file as per Rule 6(7) and kept it open for inspection by the interested parties. All parties who made request for inspection, in writing, were allowed to inspect the public file;

(xii) The Authority sought and verified information deemed necessary for the investigation, and the investigations were carried out at the premises of Petitioner's as well as cooperating Exporter from European Union.

(xiii) The Authority also conducted cost investigation to work out optimum cost of production and cost to make and sell subject goods in India on the basis of Generally Accepted Accounting Principles based on the information furnished by the petitioner.

(xiv) The investigations covered the period of 1<sup>st</sup> April, 2001 to 31<sup>st</sup> December 2001 (9 months);

(xv) The Authority provided an opportunity to all interested parties to present their views orally on 17.09.2002. All parties presenting views orally were requested to file written submissions, of the views expressed orally. The parties were advised to collect copies of the views expressed by the opposing parties and offer rebuttals, if any.

(xvi) In accordance with Rule 16 of the Rules supra, the essential facts/basis considered for these findings were disclosed to known interested parties and comments received on the same have been addressed suitably in the final findings.

(xvii) \*\*\* in this notification represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules;

(xviii) Following abbreviation have been used in the findings: PHPG Base as

D(-) Alpha Para Hydroxy Phenyl Glycine or

D(-) Alpha Para Hydroxy Phenyl Glycine Base or

D(-) Para Hydroxy Phenyl Glycine or  
Para Hydroxy Phenyl Glycine or  
D(-) P-Hydroxy Phenyl Glycine Base or  
D(-) P-Hydroxy Phenyl Glycine, etc.,

**B. Views of Petitioners, Exporters, Importers and Other Interested Parties:**

**3. Product under Consideration and Like Article**

**Views of Importer : M/s Torrent Gujarat Biotech Ltd.(TGBL), Vadodra**

(a) We do not agree with the views of Domestic Industry regarding product under consideration and like article and wish to submit as under:

It is to be understood that PHPG Base goes into direct manufacture of life saving drugs and forms part of the molecule. Any deviation in quality will hamper the efficacy of the drug. The PHPG is analysed critically for its quality. It is to be noted that the rejection is due to:

- 1) Presence of foreign material
- 2) Colour – off white colour resulting lower transmittance
- 3) Moisture content beyond specified limit.

The quality of the imported PHPG Base is generally superior than the quality of the PHPG Base indigenously available. This fact can certainly be established by comparing the quality of the material imported from various sources with indigenously available material. The specifications and its permissible limit of the various users will not necessarily be the same and may vary from user to user. Every user will have their own method of testing of the materiel and thus, the acceptance of the material by one or two users does not necessarily certify the acceptance of the quality of such an important raw material by all. The views of the domestic industry of getting repeated orders for the material from some of the large consumers are not necessarily indicative about the quality of material. Our experience on quality of the material being manufactured by M/s. DOL (Daurala Organics Limited) are totally contradictory to the claim of manufacturer.

(b) We, therefore, once again appeal to you that in the interest Amoxycillin manufactures and in the national interest; levying anti dumping duty on PHPG Base imported form European Union may kindly be reconsidered. We look forward to your kind consideration of the above matter.

#### 4. Views of the Domestic Industry

The product involved in the present investigation is D(-) Para Hydroxyl Glycine Base irrespective of its customs subheading as mentioned in the initiation notification also. It is classified in "others" category under custom subheading 2942.00 of the Customs Tariff Act (2942.00.29 under ITC). It is primarily used for production of Amoxycillin. However, it cannot be used directly. The product is first converted into "D(-) Para Hydroxyl Phenyl Glycine Methyl Potassium Dane Salt" commonly referred as PHPG Dane Salt and then used for production of Amoxycillin. There is no material difference in the PHPG Base imported from the subject countries and the PHPG Base produced by the Indian industry in terms of product specifications, function & uses, marketing, pricing, customer perception and tariff classification. PHPG Base produced by the Indian industry and PHPG Base exported from the subject countries are substitutable with each other. Therefore, it is submitted that PHPG Base produced by the domestic industry is a like article to PHPG Base imported from the subject countries within the meaning of the Anti Dumping Rules.

As regards Quality issue, the domestic Industry has submitted that they have been supplying PHPG Base to various customers who have submitted certificate of suitability of their intermediates to various Authorities not only in Europe but also in USA. They have also submitted that they have got repeated orders for some of the large customer of the subject goods in India and they have found that quality of the product is not only acceptable but also satisfactory.

#### 5. Examination by the Authority

(a) The product under consideration in this investigation is PHPG Base. (Para Hydroxy Phenyl Glycine Base). The subject goods is imported in India which is then converted in situ to PHPG Dane Salt(PHPGDS) as PHPG cannot be used directly for the production of Amoxycillin etc. This conversion is done either at PHPG/PHPGDS manufacturers' end or at the users' ends i.e. producers of Amoxycillin etc. It is classifiable under Chapter 29 of the Customs Tariff Act under sub heading 2942.00. As per ITC eight-digit classification PHPG is classified in "Others' categories' under chapter 29 i.e. 2942.0029. The present investigations are in respect of the product under consideration irrespective of the classification under which they are imported. Customs classification is

indicative only and is in no way binding on the scope of the present investigation.

(b) Rule 2(d) of the anti dumping rule specifies that Like Article is an article, which is identical and alike in all respects to the product under investigation or in absence of such an article, another article having characteristics closely resembling those of the articles under examination.

c) The petitioner has claimed that the goods produced by them are like articles to the goods originating in or exported from subject country. No dispute has been raised on the definition of the product under consideration by any interested party in the investigation. The Authority notes that PHPG base produced by domestic industry has characteristics, which are similar to those of the PHPG base imported from subject countries. No evidence has been placed by any of the interested parties regarding the fact that imported products are not substituting the domestically produced subject goods and unquantified quality difference does not make the product different. The Authority has determined that PHPG Base produced and sold by Domestic Industry and those imported from the subject countries are being used interchangeably by the consumers in India. In view of the above, the Authority holds that PHPG Base produced by the domestic industry and those being imported from the subject countries are Like Articles within the meaning of the rules for the purpose of injury determination. The Authority proposes to confirm the Preliminary Findings on Product Under Consideration and Like Article.

#### C. Initiation, Standing and Domestic Industry:

6. As per Rule 2(b) of the Anti Dumping Rules, "domestic industry means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in which case such producers shall be deemed not to form part of domestic industry."

The definition of Domestic Industry given above is further clarified by Rule 5 of Rules which reads as follows:-

“----- the application shall be deemed to have been made by or on behalf of the domestic industry, if it is supported by those domestic producers whose collective output constitute more than fifty percent of the total production of the like article produced by that portion of the domestic industry expressing either support for or opposition as the case may be to the application.

The petition has been filed by M/s Daurala Organics Limited, Daurala, Meerut, U.P. The petitioner is the sole producer of the subject goods in India. Accordingly, the petitioner satisfies the criteria of standing to file the petition on behalf of the Domestic Industry in terms of Rule 5(3) (a) of the Rules supra.

D. Period of Investigation

7. The Authority has taken POI from 1<sup>st</sup> April 2001 – 31<sup>st</sup> December 2001 being the most recent period for the investigation when this case was initiated on 15<sup>th</sup> February 2002. This period was also taken because of the closing of the quarters and the feasibility of getting the complete data. The Authority confirms that nine months time is adequate and just for Anti Dumping Investigation since it also synchronizes with the three quarters for which the relevant data could be available.

E. Other Views: Views of Importer M/s Torrent Gujarat Biotech Ltd

8. TGBL is manufacturing and exporting life saving drugs like Pencillin-G and its derivatives viz. Amoxicillin Trihydrate, Ampicillin Trihydrate, Cefalexin Monohydrate, Cloxacillin Sodium, Cefadroxyl Monohydrate. The manufacturing facility is located at Village Masar, a backward region in the District of Vadodara, Gujarat State.

Pencillin based antibiotics and in particular Amoxicillin Tryhydrate is the cheapest drug widely used in most of the developing countries. The estimated production of Amoxicillin Tryhydrate in the country is in the range of 4500/5000 MT per annum.

Up-till now PHPG Base is being imported from Europe, Singapore and China PR, as no reliable domestic source of material is available ensuring consistent quality and quantity supply. Since imposition of Anti-dumping duty on PHPG Base from China PR & Singapore, we are left out with no other alternative except to depend on the material imported from the European Union. Levying of anti dumping duty from EU would make the availability of PGPG Base scarce to meet with the domestic and export requirement of Amoxycillin Trihydrate.

The quality of PHPG Base of M/s. Daurala Organics Limited is not consistent and the product is yet to be stabilized for consistent quality. The quality of Amoxycillin Tryhydrate is directly related to the quality of PHPG Base and other raw materials.

Indian manufacturers have been importing PHPG Base @ US \$ 12/13 from Europe. The difference in prices between the two sources could be due to ocean freight, marine insurance, handling charges and other trade practices and the process technique being followed.

Proposed imposing of the anti dumping duty on PHPG Base from EU at almost double the price @ US \$ 21.38/21.81. This will increase the total cost of production of Amoxycillin Tryhydrate, which cannot be passed on to the end users.

This will also lead to Monopolistic situation in the domestic market as there is only one supplier of the product and all Amoxycillin manufacturers in India will have to either import material with antidumping duty or use domestic material at a high price and questionable quality.

The cost of production of the DOL also depends on the scale of operation and other input cost like utility, labour cost and interest. It is a know fact that the utility cost and interest rates are very high in India as compared to other countries.

In view of the above, we say that:

- a. There is no justification for fixing the arbitrary landed prices of US \$ 21.38/21.81 per kg for PHPG Base imported from European Union.
- b. It is incorrect to conclude that PHPG Base has been exported to India from European Union below its normal value.
- c. It is incorrect to conclude that the domestic industry has suffered material injury on account of imports from European Union, which could possibly be due to their inherent inefficiencies, scale of operation and higher input costs leaving aside a questionable consistent quality.
- d. On the contrary, if antidumping duty is imposed, the Indian Amoxycillin manufacturers would be put to lot of hardships and uneconomical business conditions. It would not be possible to pass on entire impact of increase in cost to end-users.

#### Comments of the Importer M/s TGBL, Ahmedabad after Disclosure

With the imposition of Anti Dumping duty, the domestic manufacturer of the Amoxicillin trihydrate will have to purchase the raw material from the local supplier by compromising with the quality. Otherwise the domestic manufacturer would have to import the same material with the additional cost of ADD. The importer has further added that this would encourage the monopolistic situation but would also increase the price of even the domestic material in near future.

F. Other view: Views of exporter: M/s Recordati, Italy

9. We produce the PHPG via enzymatic route (Petitioner's route is chemical) since 20 years and re-selling to Indian market at an average price in line with world market price. The price level of our PHPG in India comes from hard negotiations where the quantity per order and international prices of Amoxy and Pen G are closely taken under consideration.

The continuous price erosion of both PHPG and Dane Salt in 2001 has been enhanced by the presence of several Chinese new producers of these commodities. Latter's, it is well known, concentrated their export activity to India rather than elsewhere.

As per existing scenario in the market of PHPG and Dane Salt in the last few years, we never considered (you gave us the information) that a local company – the Petitioner – invested to enter the now overcrowded market of PHPG manufacturers.

We do not want to express any judgment on the Petitioner's decision for his investment, however, are deeply disappointed to ascertain that Authorities in India are called for patronage and to act against the interests of a foreign company.

Our approach to the market in India has always been correct, serious and in the spirit of fair competition. We assure you that we have not neither the resources to be burnt in an operation of dumping nor the intention to act against the interest of the Petitioner whom we require to reconsider his position.

Examination by the Authority

10. As regards the claim of the importers about the subject goods not being exported below its normal value, the Authority observes that this issues concerning sales under ordinary course of trade and exports below normal

value could be determined by the response from the exporter and not from the assertions of the importers.

As regards the observations made by another exporter M/s Recordati, on para 1.12 above, the Authority notes that adequate opportunity had been granted earlier to M/s Recordati to enable it to respond to the Authority. However the Authority notes that the exporter has not responded to the exporters questionnaire and has not submitted any data to the Authority in the present Anti Dumping Investigations. In the absence of any response from the exporter, the Authority has been constrained to treat M/s Recordati as uncooperative in the present investigations and has taken data pertaining to the exporter as per best information possible as per Article 6(8) of the Agreement of Anti Dumping and as per Rule 6(8) of the Anti Dumping rules.

#### G. Examination by the Authority regarding Monopoly, and Other Issues raised

11. It has been recognized by the Authority consistently that the imposition of anti dumping duty may have some impact on the prices of the product in the market. However, at the same time, the Authority has consistently held that the relative competitiveness of the users would not be affected with imposition of anti dumping duty. In the long run, Users would have assured supply of material at reasonable prices.

1. The fact that there is a single producer of subject goods in the country and does not, in any way, restrict the right of domestic producer to claim relief from the Authority against the dumped imports under anti-dumping rules. It has been the accepted that anti-dumping duty is in the nature and form of providing a remedy against trade distorted practice of dumping. Further, anti-dumping duties do not propose to restrict or block imports from any sources and, therefore, the issue of domestic supply being short of the total consumption in the country, has no relevance. Also, since alternative sources of supply are available to the Indian users, the apprehensions of user industry, in this regard, are misplaced.
  
2. With regards the point raised by various interested parties about domestic industry being an inefficient supplier of the subject goods, the Authority holds that it has determined injury margin considering the optimum costs of the production.

#### 12. Issues relating to the Dumping Margin

##### Views of Exporter M/s DSM Deretil

DSM Deretil is extremely shocked to note from the preliminary finding that the Authority had determined a provisional dumping margin of 6.68%. This finding is totally incorrect, illegal and arbitrary, without any basis whatsoever. The dumping margin has been contrived because of (i) arbitrary selection of the third country for determination of normal value, (ii) the arbitrary disallowance of the ocean freight indicated to India, and (iii) a deduction of 3% from the export price towards commission. According to Explanation (c)(i), the normal value is the comparable price in the ordinary course of trade for the like article sold in the exporting country or territory. If there are no sales of the like product in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporter (as in the present case), then Explanation (c)(ii) provides two alternatives for determination of normal value. Explanation (c)(ii)(a), which is relevant, provides for the determination of the normal value with reference to the comparable representative price of the like article when exported to an appropriate third country. In other words, if there are export sales to more than one third country, there is a duty cast on the investigating authority to determine which country should be used for determining the normal value. The country so determined should satisfy the requirement that it is an "appropriate" third country and the price to that country is a "representative" price. DSM Deretil had exported PHPG to India and to two other countries in the world. It had not sold PHPG to any other country, including their own domestic market (EU). The question, therefore, is which of the two third countries should be used for determining the normal value. The Authority has arbitrarily taken one of the two countries, presumably because the price to that country is marginally higher than the price to India.

Without prejudice to the above submission, it is submitted that the price to the third country considered by the Designated Authority is higher than that of India by about 1%. Such a marginal price difference cannot result in the dumping margin being above the de minimis level of 2%. DSM Deretil reiterates its submission that the export price to the other third country should be used for determining the normal value.

DSM Deretil had exported only one consignment of the subject goods to India during the period of investigation. The Authority had accepted this export price and also the deductions claimed therefrom, excepting for two deviations. In fact, these two deviations have resulted in the dumping margin. The two deviations are in respect of (a) ocean freight and (b) commission. DSM Deretil had claimed a deduction towards ocean freight. DSM Deretil had attached the invoice issued by the shipping company giving details of the ocean freight and other expenses. In other words, the actual evidence towards payment of the amount claimed as deduction on account of ocean freight was attached to the initial Questionnaire response itself. There cannot be a better evidence than the actual invoice raised by the shipper.

The Authority will appreciate that ocean freight does not depend solely on the distance travelled. It depends on the frequency of movement of ships/vessels between two ports. The number of vessels that travel between Barcelona and India is far more than the number of vessels that move between Barcelona and the third country chosen by the Designated Authority. Consequently, the freight to India and to other ports to which there are frequent shipments is considerably lower than the freight to infrequent destinations.

The Authority will note from the said invoice that the inland transport from Nhavasheva port to New Delhi is approximately equal to the ocean freight to India. The distance between Barcelona and Nhavasheva is certainly far greater than the distance between Nhavasheva and New Delhi. On this ground, the Authority cannot reject either of the transportation figures.

It is seen from para 17 of the preliminary finding that the Authority has made a deduction towards commission. The rate at which the deduction has been made has not been indicated. It appears that the Authority has made a deduction of 3% of the c.i.f. price towards commission.

In Appendix 4 of the response, the DSM Deretil had categorically indicated against the Head "Discounts/Commission", the figure of " O ". When the exporter, who knows the facts, indicates clearly that no commission has been paid it is not known on what basis the Authority has presumed that commission has been paid. This action is again clearly in violation of the principles of Natural Justice. It appears that this deduction has been made with the singular objective of somehow determining a dumping margin for DSM Deretil.

DSM Deretil does not sell PHPG Base either in Spain or in the European Union. Hence, it does not have any domestic sales. It has sold PHPG Base only to India and to two other countries in the world. The transaction-wise details of the exports made to the two countries have been made available to the Designated Authority.

It has been alleged that DSM Deretil had not disclosed its selling arrangement, but only relevant evidence has been provided. It is pertinent to point out that DSM Deretil had exported only one consignment to India during the period of investigation. The relevant evidence for this transaction has been made available which is also the evidence of selling arrangement. The write-up portion of selling arrangement is relevant only when there are several sales, made to different types of customers, with different terms of delivery/payment etc. This is not so in the case here. The only supply has been made to an end-user and copies of the indent, invoice, etc. have been made available as part of the response. The exporter had made a categorical

statement that no commission has been paid to any one on this sale transaction.

The submission that DSM Deretil has "now disclosed" that the material was delivered to ICD, Delhi is totally wrong. This information was made available as part of the original questionnaire and the DA is aware of it.

The averment in para 5 that the sales made to the Gulf country should be considered for determining normal value is totally incorrect. Para 6(i) of Annexure-I to the Anti-dumping Rules provides that comparison should be made in respect of sales made at as nearly as possible the same time. Para 6(iv) also provides that the dumping margin should normally be determined on the basis of a comparison between the weighted average normal value and the weighted average export price. The calculation of a weighted average presupposes the consolidation of all transactions that took place during the nine months of the period of investigation. Para 6(iv) also provides that the dumping margin can be determined on a comparison of the normal value transaction with the export price transaction. Both the provisions, i.e., Para 6(i) and 6(iv) have to be read harmoniously together. The Authority had determined the dumping margin on the weighted average to weighted average method and not by the transaction-by-transaction method.

The appropriate third country has to be determined with reference to the market conditions prevalent in India and that of the third country. The representativeness of the price is required to be determined with reference to the conditions of competition in the two countries.

The allegation that the cost of production made available by the exporter "is highly suspected" is objectionable. As regards Balance Sheet and Profit & Loss Accounts for POI, the Authority is very well aware, having conducted more than ninety investigations, that no company ever prepares a profit and loss account and balance sheet for the period of investigation set by the Authority or for the product being investigated. The cost of production submitted by us is very much backed by the evidence and is open to verification by the Designated Authority.

The response submitted by DSM Deretil is sufficient and reliable. We have made available all reasonable and sufficient information that has been asked for by the Authority till date. Hence, we request the Designated Authority to verify this information and reverse the finding in so far as DSM Deretil is concerned.

#### Comments by the exporter after Disclosure statement

They have saked investigation to be terminated as dumping margin is De-minimus. Also they have also added that \*\*\*\* is more appropriate than \*\*\* for

the determination of the normal value.

#### H. Views of domestic Industry

13. The company has not furnished transaction wise export details to other countries. Since the exporter has claimed that there is no domestic sales of the exporter, the exporter was obliged to provide details transaction-wise details of exports to third countries. It is relevant to note that unless the exporter provides transaction wise details of exports to other countries, it cannot be established by the exporter that its sales in other countries were in the ordinary course of trade.

The exporter has not disclosed its selling arrangement. Only relevant evidence has been provided on confidential basis. However, the write up part has been simply ignored by the exporter. The reply to the questionnaire is deficient to such an extent. Thus, petitioner is at loss to understand how the exporter has done business. This all the more important in view of the claim of the exporter that it has paid no commission in respect of all the sales. Exporter has now 'disclosed' that the material was exported by the company, delivered ICD-Delhi. Invoice referred by the exporter at the time of oral hearing disclosed that the same contained ocean freight from European Union to Mumbai and inland freight from Mumbai to Delhi. This revelation by the exporter raises a major issue with regard to the quantum of deduction made by the exporter from the CIF export price. The freight (ocean and inland) from EU port to Delhi is quite higher as compared to Ocean freight from European Union to Mumbai. The petitioner requests detailed investigations on this account.

Petitioner constructed the freight claimed by the exporter in case of exports to two other countries. It was rather shocking for the petitioner to find that the exporter has claimed an estimated freight in case of the Gulf country, which is almost five times higher than ocean freight involved in case of India. By no stretch of imagination, the freight from the exporter's port to Gulf port can be so high as claimed by the exporter. It is for this reason that petitioner has been repeatedly insisting on evidence of freight in this regard. However the exporter has consciously avoided providing this information.

With regard to the argument of the exporter that assessment of normal value should be based on Country 1, petitioner submits that normal value should be based on export sales from European Union to country 2. The sales made to country 2 were in same period of time as was in respect of exports to India.

The cost of production information provided by the exporter is highly suspected by the petitioner. Further, the information has been restricted only

to PHPG Base and information in respect of other products has not been provided.

The exporter has not provided Balance Sheet and Profit & Loss Statement for the investigation period. Further, P&L Statement is not for the product under consideration. It is relevant to note in this regard that the company is a multi product company. Thus, allocation and apportionment basis used by the company assumes greater importance. It is possible that some elements of cost are affected due to certain affiliations. Thus, a mere statement filed by the company cannot be accepted by the Designated Authority without calling necessary information and thereafter verifying the data. Petitioner, therefore, submits that the detailed information on cost of production is required to be collected from the exporter.

M/s. Recordati, Italy has not furnished information in the form and manner prescribed by the Authority. The same is evident from the preliminary findings also. Therefore, Designated Authority is fully justified in proceeding with best available information. Recordati is the major exporter of PHPG Base from EU to India. Against total exports of more than 144000 kgs. exported to Indian in the investigation period, exports by DSM was just 9000 kgs. Thus, it can be stated that the majority exporter of the subject goods from the subject countries have refrained from responding to the Designated Authority.

#### Comments of the Domestic Industry after the Disclosure

1 M/s DOL, has submitted that assuming , though not admitting, that the company did not pay any commission to this indent, the fact that the order was procured through an indenting agent, adjustment of the amount of the commission which is payable as consideration against such services rendered by the agent is required to be made.

2. The domestic industry has added that if there is any change in the in the exporters submission towards Appendix 7 as well as in the information relating to the Appendix 8,9 and 10, the complete response of the exporter should be rejected.

#### I. Examination by the Authority

14. Under Section 9A(1) (c) normal value in relation to an article means:

(i) The comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article when meant for consumption in the exporting country or territory

as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or

(ii) When there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either:

(a) Comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or

(b) The cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6)";

Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely transshipped through the country of export or such article is not produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin.

M/s DSM Deretil, S.A. Spain.

#### 15. Normal Value

M/s. DSM Dereteil has replied that they have no domestic sales. They have given information in their response to their questionnaire in the prescribed format. As per Appendix –1 they have replied that they do not have any domestic sales and they have also added that they don't have any sales in the European Union for that product. As per Appendix –3 they have given an account of their sales to other countries and India, which is further split in month wise details of the sales. In the Appendix-4 & 6 they have given price structures and sales arrangements for sales to India and other countries. The Authority had noted at the time of preliminary findings that the exporter had not submitted complete information with respect to appendix 7, of the exporters' questionnaire. Additionally, complete information with respect to finance and interest costs with respect of appendix 8 and 10 had also not been furnished by the exporters. Though the exporter had submitted month-wise information for exports to third countries in

aggregate, they had not submitted country-wise and transaction wise information with respect to third country exports.

After the preliminary findings, the exporter has furnished complete information with respect to the Appendix-7 of the exporters questionnaire. The exporter has also submitted transaction-wise information with respect to third-country exports during the period of investigation. Information with regards to the quantity and value for other products has also been submitted. After the preliminary findings, they have submitted information relating to financial and interest costs pertaining to Appendix 8 and 10 of the exporters questionnaire. They have also submitted their corporate balance sheets and profit and loss accounts for the last three years. In response to the submissions made by the domestic industry after the disclosure, the Authority notes that these submissions have been made by the exporter subsequent to the public hearing and all submissions received before the Authority have been examined by the Authority in this final findings.

The Authority notes that firm has submitted detailed information regarding the sales price structure for the exports to other countries and India. The Authority also verified the original documents at the exporters premises pertaining to the transaction wise details of exports made to other countries. The verification team examined the evidence in support of the claim made by DSM Deretil for the freight paid on the consignment exported to India and for non-payment of any commission on this transaction. The verification team also examined ordering system prevalent in DSM Deretil and also examined the ledger accounts of importer in India. Ledger account of the indenting agent was also verified by the verification team for the POI and after that period to examine the commission paid if any by the exporter. The verification team also examined the invoices raised by the M/s Global Container Agency-S.A for shipment to India and other countries. The verification team also examined the reasonableness of the ocean freight and freight from Nhava Sheva to New Delhi by examining the other invoices for this period pertaining to other products. The verification team also examined the methodology for reporting the figures of POI for ascertaining the cost of production data.

On the basis of above examinations, the Authority has determined the normal value for this exporter by taking Comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory. The Authority has determined that M/s DSM has exported \*\*\*\* kg of subject goods during the POI for US\$\*\*\*\* to country \*\*\*\*. The Authority has accepted country Iran as an appropriate third country as exports have been made to that country around the same time as exports made to India. As per section 6(1) of the Annexure-1 to the Anti

Dumping rules, "while arriving at margin of dumping, the Designated Authority shall make a fair comparison between the export price and normal value. The comparison shall be made at the same level of trade, normally at ex-factory level and in respect of sales made at the same level of trade, normally at the ex-factory level and in respect of sales made at as nearly as possible the same time. The Authority had observed that the sales were made to the country "IRAN", at the same time, when they had shipped the goods into India. The Authority had also taken IRAN as the appropriate third country as its level of development and economic parameters are more in the line of country of export. The Authority has determined weighted ex -factory price of US\$ \*\*\*\*/kg for exports to country IRAN after deducting US\$\*\*\*\*/kg for packing, US \*\*\*\*/kg for the inland freight, US\$ \*\*\*\*/kg as inland insurance, US\$\*\*\*\*/kg for the overseas freight, US\$ \*\*\*\*/kg for the overseas insurance. The normal value determined for this exporter is US \$ \*\*\*\*/kg.

#### EXPORT PRICE:

16. The exporter has exported \*\*\*\* Kg. of PHPG Base to India for a total value of US\$\*\*\*\*. They have given transaction wise details for export sales made to India in their response to the exporters questionnaire. Accordingly, the weighted average export price of PPHPG during the period of investigation works out to US\$\*\*\*\* per kg. After verifying the exports data for this firm for exports to India with regards to commission and freight, the Authority has determined the weighted ex-factory price for export sales to India as US \$ \*\*\*\*/kg after making adjustments on account of inland freight @ US \$ \*\*\*\*/kg, packing @ US\$ \*\*\*\*/kg, inland insurance @ US \$ \*\*\*\*/kg, overseas freight @ US \$\*\*\*\*/kg, overseas insurance @US \$ \*\*\*\*/kg, shipping charges @ US\$ \*\*\*\*/kg, clearance and handling charges @ US\$ \*\*\*\*/kg.

Dumping Margin has been established on the basis of comparison of the weighted average normal value with weighted average export price. The dumping margin in case of M/s DSM Deretil S.A. from Spain is assessed by Authority at US\$ \*\*\*\* per Kg or 1.21% of the export price., ,

#### M/s Recordati, Italy:

17. M/s Recordati has given only a general submission and have commented only on the technology used by them and by the Petitioner. They have not submitted any data/information in the form and manner prescribed in the Exporters Questionnaire and have not presented any data relating to the various Appendices mentioned in the exporters questionnaire. The Authority, therefore, considers the exporter to be non-cooperative. As no information/data about

domestic sales price structure of the subject goods, its cost of production in EU and other information as per the questionnaire was furnished, it is not possible to determine the normal value in the ordinary course of trade as per the WTO provisions and the Anti Dumping Rules. The Authority has, therefore, been constrained to rely upon the best available information for the determination of normal value. The petitioners have claimed normal value in respect of EU on the basis of constructed cost of production. This has been considered by the Authority in the absence of the data on the cost of production & domestic sales transactions. The Authority has determined Normal value on the basis of the facts available to it as per rule 6(8) supra.

The normal value so determined for M/s Recordati, Italy is US \$ \*\*\*\* per Kg.

As regards determination of export price from M/s. Recordati, the Authority notes that \*\*\*\* MT of subject goods have been exported for US\$ \*\*\*\* from EU at the unit price of US\$ \*\*\*\*/kg during the POI. The Authority has determined the weighted ex-factory export price as US\$ \*\*\*\*/kg after making adjustments on account of inland freight, insurance, overseas freight, Commission and overseas insurance as made in case of M/s Deretil, DSM, Spain.

Thus, the dumping margin in case Recordatti is assessed by Authority at US \$ \*\*\*\* per Kg. or 78.48 % of export price.

#### OTHER EXPORTERS FROM EU

18. The Authority provided opportunity to the known exporters from EU to furnish information relevant to the investigations and offer comments, if any, in accordance with the Rules cited above. The Authority notes that none of the exporters apart from those mentioned above from the EU have filed any response and furnished information on domestic sales price structure of the subject goods, its cost of production in EU and other relevant information as per the questionnaire. In the absence of information/data, the Authority has proceeded to rely upon the best available information for determination of normal value. The petitioners have claimed normal value in respect of EU on the basis of constructed cost of production. This has been considered by the Authority in the absence of the data on the cost of production & domestic sales transactions.

Accordingly, the Authority has constructed the normal value on the basis of facts available as per Rule 6(8) with the applicable adjustments. The normal value so determined for other exporters from EU is US \$ \*\*\*\*/kg.

The Authority has assessed the export price at the ex factory level for other exporters as has been done in the case of M/s Recordati , Italy and thus the weighted average export price at the ex-factory level comes to US\$ \*\*\*\*/kg after making all adjustments as made in the case of M/s DSM Deretil, Spain.

Thus, the dumping margin in case of non-co-operative/other exporters of PHPG Base from EU is assessed by Authority at US\$ \*\*\*\* per Kg. or 78.48% of the export price.

Exporters/Country/Territory	Normal value	Export price	Dumping Margin % of Export price
DSM Deretil, Spain	****	****	1.21
Recordati, Italy	****	****	78.48
Other Exporters from EU	****	****	78.48

#### J. Issues relating to the Injury

##### Views of the Exporter, M/s DSM Deretil, Spain

19. Section 9B, inter alia, provides that the anti-dumping duty shall not be levied on import of any article into India from a member country of the WTO unless a determination has been made that the import of such article into India causes or threatens material injury to any established industry in India or materially retards the establishment of any industry in India. It is pertinent to point that that Section 9B contemplates three mutually exclusive injury determinations. These are:-

- (a) actual material injury; or
- (b) threat of material injury; or
- (c) material retardation to the establishment of an industry in India.

The existence of actual material injury during the period of investigation would by definition exclude threat of material injury or material retardation. The absence of actual material injury during the period of investigation may

still result in the imposition of dumping duty if there is a finding that there is a threat of material injury, in future. Material retardation does not take into account either actual present material injury or threat of future injury. It deals with a situation where a domestic industry manufacturing the like product is being attempted to be established and this attempt is materially retarded because of the allegedly dumped imports. Thus, the three types of injury are mutually exclusive. It may be seen from the finding that there is no clear indication as to which of these three aspects has been found to exist in this investigation.

Further, all the 15 factors that are mandatorily required to be examined for injury purposes have not been evaluated.

The establishment of the causal link has been superficial. It is seen from para 24(a) of the preliminary finding that the average import price from European Union in September 2001 is US \$ 11.816 per kg. The export effected by DSM Deretil is in July 2001 at a price, which is far higher than the price indicated in para 24(a). In para 24(e), the Table shows a fall in the net realisation, during the period of investigation, for the domestic industry. It is seen that the net realisation has fallen from about 100 in June 2001 to about 80 in September 2001. It is pertinent to note that the price had fallen to 89.47 in July 2001 and 91.42 in August 2001, whereas there has been no import of this product during these months from the European Union. This shows that the fall in price in July and August has not been influenced by the imports from the European Union. If that were so, it is not known on what basis the fall in price from August 2001 to September 2001 is being identified as caused by European Union. It is our submission that the fall in net sale realisation has not been made by European Union, more particularly by DSM Deretil.

It is seen from the preliminary finding, in the present investigation, that the reference price for all other exporters other than DSM Deretil is US\$ 21.81 per kg. This again shows that US\$ 21.81 is the NIP for the domestic industry. A comparison of these two figures shows that the cost + profit for the period 1st April, 2001 to 30th September, 2001 is US\$ 24.83 whereas it is US \$ 21.81 for the nine month period 1st April, 2001 to 31st December, 2001. The NIP had fallen by about 12%. Since the average of the six-month NIP (US\$ 24.83) and the three-month NIP would be US\$ 21.81, it is axiomatic that the NIP for this three month (October-December, 2001) period must be much lower than US\$ 21.81 in order that a weighted average of US\$ 21.81 could have been arrived at for the nine month period. This shows that the choice of the period of investigation, coinciding with the commencement of the commercial production, which is bound to be at a low capacity utilisation and high initial cost, has resulted in a high NIP. The determination of NIP requires a re-look in order to adjust for the abnormal/start up cost associated with initial operation. It appears that the domestic industry is

taking undue advantage of the anti-dumping proceedings in order to protect itself from the normal teething troubles that arise during the initial phase of any newly set up industry.

We request the authority to determine NIP on a quarterly basis and compare the landed value of imports from DSM Deretil with the NIP for the quarter October - December 2001. In fact, in the present case itself, the Designated Authority has considered domestic sales realisation on a month-to-month basis. The Designated Authority should consider cost of production on a monthly basis and the NIP at least on a quarterly basis.

During this period, NIP for the domestic industry was approximately US\$ 15.77 per Kg, whereas the landed value from EU was much higher than the NIP. In fact, the landed value of exports from DSM Deretil was higher than the NIP by over 25%. As such there was no undercutting by DSM Deretil.

It is also necessary to determine price undercutting with reference to individual exporters and not in totality. The landed value of DSM Deretil is available to the Designated Authority. The NIP for the period October-December is also available. This would clearly show that the landed value of DSM Deretil is higher than the NIP.

20. To conclude, we submit on behalf of DSM Deretil that:

- (i) the comments of the domestic industry are mostly wild allegations and figments of imagination that need to be completely disregarded;
- (ii) The export price of DSM Deretil has not caused any material injury to the domestic industry; and
- (iii) the investigation requires to be terminated on both the absence of dumping margin and causality.

#### K. Views of the Domestic Industry

21. Dumped imports from China and Singapore were earlier causing injury to the domestic industry. The Designated Authority was kind enough to recommend anti dumping duties on imports from these countries, which have since been imposed by the Govt. of India. Therefore, injury to the domestic industry is required to be examined in the light of existing anti dumping duties in force. The dumped imports have been threatening further material injury to the domestic industry. It is also relevant to point out that the petitioner has commenced commercial production only with effect from April 01, and

therefore, all parameters relating to the injury of the domestic industry would have to be seen in the light of this short commercial history of the domestic industry.

Imports from subject countries have increased in absolute terms. The share of imports from European Union has increased significantly during the Period of Investigation. The imports from European Union, which were nil up to August 2001, started coming in huge volumes. This may be due to the fact that Designated Authority had initiated the investigations into subject goods from China and Singapore in October 2001. This is in spite of the fact the domestic industry had just commenced commercial production. The exporters from subject countries have reduced the prices and intensified during to gain market share in India and thus materially retarded the establishment of domestic industry at its nascent stage. The domestic industry could not optimize its capacity, which it could have otherwise achieved in the absence of dumped imports. The sales of the domestic industry have not increased in spite of increase in demand. The selling price of the domestic industry has declined during the period of investigation due to availability of dumped imports to the consumers, albeit with changed sources. The exporters from the subject countries have significantly reduced prices. The domestic industry has lost sales, as imports of subject goods are available at dumped prices. The domestic industry has a tendency to retain its employees. Further, the petitioner has set up new facilities for the subject goods. However, should the present trend continue, the domestic industry will be forced to curtail its employment level. The domestic industry has reduced the already sub-optimal selling prices to match the landed price of the exports resulting in losses. The domestic industry could not sell at the prices which can recover even its cost of production leave aside fair return on capital employed. It may thus, be seen that the domestic industry has suffered material injury. Further, the domestic industry is threatened with material injury due to dumped imports. Equally important to note is that since the domestic industry has commenced commercial production only recently, the imports are retarding establishment of the domestic industry.

#### EXAMINATION BY AUTHORITY

##### L. INJURY:

22. Under Rule 11 supra, Annexure –II, when a finding of injury is arrived at, such finding shall involve determination of the injury to the domestic industry, ".... taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles...." In considering the effect the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether

the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree.

For the examination of the impact on the domestic industry in India, the Authority also considered such further indices having a bearing on the state of industry as capacity utilization, production, sales, net sales realization, profitability, etc. The Authority took into account various parameters indicating injury to the domestic industry, which are as follows:

#### (a) Quantum of imports and export price

The information with regard to the quantum of imports of the subject goods has been based on the statistics compiled from Customs Daily Lists. The Authority notes that there has been an increase of 562.5% in the volume of imports of the subject goods from the subject countries during the Period of Investigation over 2000-01. Further the average export price from the subject countries has also declined during the Period of Investigation against 2000-01.

#### Imports from European Union

Period	Qty(MT)	Value(Rs Lakhs)	Average price Rate/US\$MT	%share of Imports
98-99	129	1850553	14259	18.82
99-00	128	1861378	14486	13.11
2000-01	24	169.01	14907.85	2.38
POI (April-December) 2001	135	749.49	11577.14	12.12
POI (2001-02) Annualised	180	999.33	11577.14	12.12

#### Month Wise imports from European Union

7/18/2003 - 6

Period	Qty(Kg)	Value(Rs Lakhs)	in Rate/US\$MT
2001			
April	Nil	Nil	Nil
May	Nil	Nil	Nil
June	Nil	Nil	Nil
July	Nil	Nil	Nil
August	Nil	Nil	Nil
Sept	45000	251.79	11816.9
Oct	Nil	Nil	Nil
Nov	60,000	332.99	11502.15
December	30,000	164.71	11367.49

b) Changes in market share held by Indian producers and imports from the subject countries:

The Authority observes that M/s DOL is the new entrant in manufacture of the subject goods in India and the exporters from subject countries have intensified dumping of the subject goods into India so as to ensure that domestic industry does not get any market share and also materially retard the establishment of the industry at its nascent stage itself.

(c) Production and Capacity utilisation of the petitioner:

THE domestic Industry has commenced production during the POI and has only achieved a utilization of \*\*\*\*% of its existing installed capacity during period of investigation. Keeping in view the demand in the country the same is far below than what could have been achieved by the Domestic Industry.

(d) Insignificant gain of market share:

Domestic industry is at nascent stage, hence no past trends are available but domestic industry is unable to increase its sales volume, in spite of huge demand of the subject goods in the country, because of dumped imports from subject countries.

**(e) Reduction in selling price, price erosion, price undercutting, price suppression or price depression:**

In order to analyze the effect of dumped imports on the selling price of the Domestic Industry an analysis of the monthly sales realisation of the subject goods has been made as under:

Period	Qty Sold/Kg	Net Realization (Rs/Kg)	Sales
April-2001	****	100	
May-2001	****	100	
June-2001	****	100	
July-2001	****	89.47	
August-2001	****	91.42	
Sepetember-2001	****	79.06	
October 2001	****	75.61	
November	****	75.72	
December	****	78.34	

Indexed Figures considering April 2001 as 100

The table above indicates that the monthly average sales realisation during the Period of Investigation has declined from \*\*\*\* Rs/ Kg. during April 2001 to \*\*\*\* Rs/ Kg. during December 2001 showing a decrease within the Period of Investigation itself. This is mainly due to decrease in the average import price by the exporters after the starting of the commercial production by the Domestic Industry.

**(f) Evidence of lost contracts or declining sales:**

It has been observed that because of the sharp decrease in the export prices by the exporters, the Domestic Industry could not gain contracts/orders at the prices which could recover the cost of production leave aside a fair return on capital employed. The petitioner could sell the subject goods at substantial losses only.

**(g) Employment:**

The domestic industry has submitted that as the industry is at its nascent stage, protection from unfair trade practice is vital and urgent otherwise the manpower deployed will loose their jobs.

**(h) Profitability:**

It has been observed that the Domestic Industry has attempted to sell the subject goods by matching the prices being offered by the exporters resulting in huge losses.

The present petition is regarding impact of dumped imports causing material retardation to the establishment of the industry. Since the petitioner is attempting to achieve commercially viable production in the Indian market and the imports from the subject territory are preventing such commercialisation of production by the domestic industry, the imports have caused material retardation to the establishment of the industry. As a "nascent industry", M/s Daurala Organics Ltd. has recently started production and is yet to find its place in the market. The Authority notes, therefore, that domestic Industry is unable to achieve a satisfactory level of capacity utilisation and find its place in the market, because, at this nascent stage the domestic industry is being threatened with material retardation, by imports at dumped prices from the subject territory.

**23. Price Undercutting and Price Underselling**

Price Undercutting during POI			
Country/Territory	Net selling Price petitioner	Landed Price from subject country	Price Undercutting
EU			

DSM, Deretil, Spain	****	****	(-)****
Recordati, Italy	****	****	****
Price Underselling during POI			
Country	Non Injurious Price of petitioner	Landed Price from Subject country	Price Underselling
EU			
DSM, Deretil Spain	****	****	****
Recordati, Italy	****	****	****

In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree. The Authority has compared the landed value of imports of subject goods from subject countries during the POI with the net sales realization and has found that there has been a significant price undercutting by the dumped imports from subject country/territory (except DSM Deretil, Spain). The landed value of imports has been found to be lower than the domestic industry's net sales realization.

The Authority has also examined the claim of the petitioner that the domestic industry is suffering on account of the losses. The Authority notes that price underselling is an important indicator to make an assessment of the injury. The Authority has worked out the Non-injurious price for the product under consideration and compared the same with the landed value to arrive at the extent of price underselling. The analysis shows a significant incidence of price underselling causing injury to the domestic industry. The imports have had significant suppressing/ depressing effect on the prices in the domestic market, as the domestic industry has not been able to raise its selling price in view of the dumped imports.

### Selling Price / Profitability

24. The authority notes that selling prices of the domestic industry is significantly below the price, which would have permitted the domestic industry, a fair recovery of its cost of production and earn a reasonable return. Thus, the dumped imports have prevented the domestic industry from effecting legitimate price increase to realize a reasonable price. The industry has suffered material injury on account of depressed selling prices resulting in non-recovery of cost of production and has therefore suffered financial losses.

The Authority has examined the contention of the domestic industry that it is facing threat of material injury apart from material injury. The Authority notes that as per 3.7 of Agreement of Anti Dumping, a determination of threat of material injury shall be based on facts, and not merely on allegation, conjecture or remote possibility. The change in circumstances, which could create a situation in which the dumping would cause injury, must be clearly foreseen and imminent. In making a determination regarding the existence of a threat of material injury, the Authority has analysed factors laid down as per 3.7(i) –(iv) of the Agreement on Anti-Dumping and as per Annexure II of the Anti Dumping Rules made under the Customs Tariff Act.

There has been a significant rate of increase of dumped imports into the domestic market from subject country during the POI over the previous year.

The petitioner has claimed that EU is having large unutilized capacity to manufacture the subject goods. Though the major exporter from EU, M/s Recordati, Italy which has exported 90% of the subject goods during the POI and which has responded to this petition, has not indicated capacity of their plant and inventory of their finished goods in their exporters questionnaire. However the Authority notes that none of the interested parties to the investigation has disputed the claim of the domestic Industry with regards to the unutilized capacity.

On the basis of these findings as mentioned above, the Authority notes that the petitioner is suffering from a further threat of injury apart from the material injury it has suffered already.

### M. CAUSAL LINK

25. In determining whether injury to the domestic industry was caused by the dumped imports, the Authority took into account the following facts: -

(I) Substantial imports of subject goods from subject countries /territories at dumped prices forced the domestic industry to reduce its selling prices to un-

remunerative level, which has resulted in a situation of price undercutting in the Indian market.

(ii) The imports from subject countries/territories suppressed the prices of the product in the Indian market to such an extent that the domestic industry was prevented from recovering its full cost of production and earn a reasonable profit from the sale of subject goods in India.

The Authority notes that imports of subject goods from the European Union during the POI accounted for 21.2% of the total imports into this country. It is also noted that dumped imports from subject territory account for more than 90% of the total imports from the European union during the POI. Imports from subject country/territory have increased from 2% of the total imports during the previous year to 21% of the total imports in the POI. Thus volume injury is clearly established. In examining the price effect, the Authority notes that the low priced imports from the subject country/territory has forced the petitioner to sell at suppressed prices and incur losses on the sale of the subject goods during the period of investigation. Dumped imports of subject goods have prevented the domestic industry from realizing a reasonable remunerative selling price in the domestic market. The domestic industry in its attempts to match the dumped import prices was forced to sell below its non-injurious price, which resultantly, the domestic industry was unable to recover.

Imports from other countries have been much less during the POI as against previous years and prices from these countries are higher. The Authority could not find any evidence of contraction of demand, change in pattern of consumption, trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers. It is also noted that developments in technology have not been a cause for injury to the domestic industry.

The landed value has been determined for the subject goods after adding onto the weighted average c.i.f. export price, the applicable level of customs duties (except duties levied under Section 3, 3(A), 8B, 9, 9(A) and 1% towards landing charges.

While determining the non-injurious price for the like articles for the domestic industry, the Authority has used the actual cost of production of the subject goods to determine optimum cost of production for the domestic industry which would take into account the normated best consumption norms and the actual price of the raw materials which are consumed for the production of the subject goods during the period of investigation. For calculation of injury margin, it is proposed to compare the ex-factory non-injurious price determined for the period of investigations with the landed value of the imported goods.

26. Duty up to dumping margin:

The Authority recommends the amount of anti-dumping duty equal to the margin of dumping or less, which if levied, would remove the injury to the domestic industry.

N. INDIAN INDUSTRY'S INTEREST:

27. The purpose of anti dumping duties in general is to eliminate dumping which is causing injury to the domestic industry and to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country.

The Authority recognizes that the imposition of anti dumping duties might affect the price levels of the products manufactured using subject goods and consequently might have some influence on relative competitiveness of these products. However, fair competition on the Indian market will not be reduced by the anti dumping measures. On the contrary, imposition of anti dumping measures would remove the unfair advantages gained by dumping practices, would prevent the decline of the domestic industry and help maintain availability of wider choice to the consumers of subject goods.

The Authority notes that the imposition of anti dumping measures would not restrict imports from European Union in any way, and therefore, would not affect the availability of the product to the consumers.

O. CONCLUSIONS:

28. The Authority has, after considering the foregoing, come to the conclusion that:

- (i) D (-) Para Hydroxy Phenyl Glycine Base has been exported to India from European Union below its normal value;
- (ii) The Indian industry has suffered material injury.
- (iii) The Domestic Industry, on account of the injury being suffered, is also facing material retardation in the establishment of new industry to manufacture D (-) Para Hydroxy Phenyl Glycine Base.
- (iv) The material injury and material retardation is on account of dumped imports from subject territory.

(iv). The Authority considers it necessary to impose definitive anti dumping duty on all imports of D (-) Para Hydroxy Phenyl Glycine Base from subject country/territory in order to remove the injury to the domestic industry. The margin of dumping determined by the Authority is indicated in the paragraphs above. The Authority proposes to recommend the amount of anti dumping duty equal to the margin of dumping or less, which if levied, would remove the injury to the domestic industry. For the purpose of determining injury, the landed value of imports is compared with the Non Injurious Price of the petitioner company determined for the period of investigation.

(v). Accordingly, the Authority recommends that the definitive Anti dumping duties be imposed from the date of notification to be issued in this regard by the Central Government on all imports of D (-) Para Hydroxy Phenyl Glycine Base also known as D (-) Alpha Para Hydroxy Phenyl Glycine, D (-) Alpha Para Hydroxy Phenyl Glycine Base, D (-) Para Hydroxy Phenyl Glycine, Para Hydroxy Phenyl Glycine Base, Para Hydroxy Phenyl Glycine, D (-) P – Hydroxy Phenyl Glycine Base, D (-) P – Hydroxy Phenyl Glycine falling under Custom Heading 2942 originating in or exported from European Union pending final determination. The Anti-Dumping duty shall be the difference between the amount mentioned in column 3 of the following table and the landed value of imports per Kg. on all the imports of subject goods falling under Chapter 29 of the Customs Tariff, originating in or exported from the subject territory/country mentioned below: -

Country/Territory (1)	Producer/exporter (2)	Amount US\$/kg (3)
European Union	DSM Deretil, Spain	NIL
	All other exporters/ Producers	21.60

vi). Landed value of imports for the purpose shall be the assessable value as determined by the Customs under the Customs Act, 1962 and all duties of customs except duties under sections 3, 3A, 8B, 9 and 9A of the Customs Tariff Act, 1975.

29. Subject to the above, the Authority confirms the preliminary findings dated 5<sup>th</sup> June 2002.

30. An appeal against this order shall lie before the Customs, Excise and Gold (Control) Appellate Tribunal in accordance with the Act, supra.

L. V. SAPTHARISHI, Designated Authority